कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qksu (dk-) : +91(11) 23381428
QSDl : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय-सूची

अमित शाह बने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष... 7

आम बजट 2014-15

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का वक्तव्य.. 11
मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का वक्तव्य............................. 15
केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का वक्तव्य.. 16
छोटा किंतु सधा कदम / **प्रो. पुष्पेश पंत**.. 17

रेल बजट 2014-15

प्रमुख बिन्दु... 18

साक्षात्कार

अरुण जेटली, केन्द्रीय वित्त व रक्षा मंत्री.. 11
सदानंद गौड़ा, केन्द्रीय रेल मंत्री.. 19

लेख

इतिहास के दागदार पन्ने
– **बलबीर पुंज**.. 23
मजबूत जनादेश की झलक
– **ए. सूर्य प्रकाश**... 25
एक और विवादित बिजनेस मॉडल
– **राजीव सचान**... 27

अन्य

भाजपा अनु.जनजाति मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी, रांची............................ 29
भाजपा बिहार प्रदेश कार्यकारिणी बैठक.. 30

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को रक्षा बन्धन (10 अगस्त 2014) की हार्दिक शुभकामनाएं!

बोध कथा

..और उसने गांधी जी के चरण पकड़ लिए

उन दिनों गांधी जी जेल में थे। उनसे मिलने ढेरों लोग रोज जेल पहुंच जाते थे, जिससे जेलर परेशान रहता था। आखिरकार उसने एक अफ्रीकी कैदी को गांधी जी की निगरानी का काम दे दिया। वह कैदी गांधी जी पर कड़ी नजर रखने लगा ताकि उनसे कोई मिल न पाए। वह जेलर की आज्ञा का सख्ती और ईमानदारी से पालन कर रहा था। वह कोई भी भारतीय भाषा नहीं समझता था।

जब कभी वह गांधी जी के पास से गुजरता गांधी जी उसे देखकर हल्के से मुस्करा देते। वह कभी मुस्कराता और कभी गांधी जी को घूरते हुए गुजर जाता। लेकिन बापू हमेशा उसे देखकर मुस्कराते थे। एक दिन वह कैदी बैरक की सफाई कर रहा था। बैरक में चारों ओर गंदगी फैली थी। अचानक एक बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। कैदी दर्द से तड़प उठा। डंक के कारण उसका शरीर धीरे-धीरे नीला और ठंडा पड़ने लगा। उसकी आंखें भी बंद होने लगीं।

यह देखकर गांधी जी तेजी से दौड़े और उस कैदी के पास गए। उन्होंने पलक झपकते ही उसका हाथ अपने हाथ में लिया और जहां बिच्छू ने डंक मारा था, उसे रगड़ने लगे। फिर उन्होंने मुंह लगाकर उसका जहर निकालने की कोशिश की। यह देखकर कैदियों में अफरातफरी मच गई। जल्दी से डॉक्टर बुलाया गया। तुरंत उसका उपचार किया गया। जब उस अफ्रीकी कैदी ने आंखें खोलीं तो गांधी जी को अपने पास पाया। गांधी जी उसी चिरपरिचित मुस्कराहट के साथ कैदी को देख रहे थे। कैदी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गांधी जी के चरण स्पर्श कर लिए। उसके बाद वह जीवन भर गांधीजी को अपना आदर्श मानता रहा।

संकलन : रेनू सैनी

(नवभारत टाइम्स से साभार)

व्यंग्य चित्र

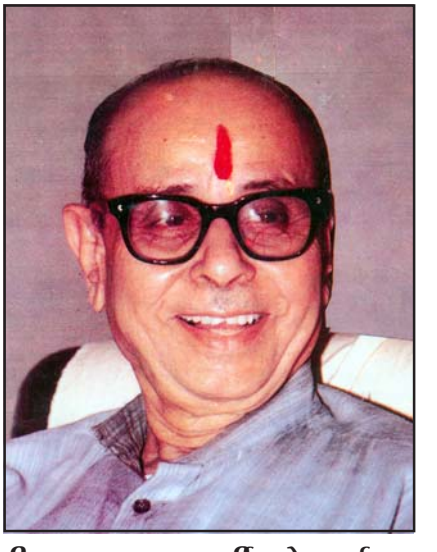

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्व. कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती (15 अगस्त) पर उन्हें सादर नमन!

सम्पादकीय

'सबका साथ–सबका विकास' है बजट का संदेश

नरेन्द्र मोदी सरकार के पहले बजट का इंतजार पूरा देश बहुत ही व्यग्रता के साथ कर रहा था। इस बजट से लोगों की अनेक आशाएं एवं अपेक्षाएं जुड़ी हुई थीं। इसमें अब कोई भी शक नहीं कि पूरे देश को बजट ने हर्षोल्लास से भर दिया। एक तरफ जहां अनेक नए कदमों की घोषणा की गई वहीं लोगों को वे राहत दिए गए, जिसका वे बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। खास बात यह रही कि इस पूरी प्रक्रिया में वित्तीय चुनौतियों को भी ध्यान में रखा गया। बजट में न केवल वित्तीय अनुशासन पर ध्यान दिया गया बल्कि एक सुदृढ़ एवं आत्मविश्वास से परिपूर्ण भारत के निर्माण के लिए भी पथ प्रशस्त किया गया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने निरंतर घटते आत्मविश्वास, खाड़ी की बिगड़ती स्थिति तथा कमजोर मॉनसून के समाचारों के बीच जनता की अपार अपेक्षाओं एवं आशाओं को पूरा करने की एक गंभीर चुनौती थी। साथ ही उन्हें कांग्रेस नीत यूपीए सरकार से विरासत में मिले कमजोर एवं ढुलमुल अर्थव्यवस्था से भी जूझना था। चुनौतियां अत्यंत विकट थी क्योंकि वित्त मंत्री को मात्र 45 दिनों में ही देश की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को पूरा भी करना था। गंभीर वित्तीय स्थिति, गिरती विकास दर, उद्योग जगत को अपने चपेट में लेती अटकी पड़ी परियोजनाएं, बढ़ती महंगाई जैसी कई गंभीर चुनौतियां सुरसा की तरह मुंह बाये खड़ी थीं। इसके साथ ही नरेन्द्र मोदी और भाजपानीत एनडीए को मिला विशाल जनादेश ने चुनौतियों को और भी अधिक गंभीर बना दिया था क्योंकि चुनावी नतीजों के तुरन्त बाद सेन्सेक्स ने भारी उछाल दर्ज किया था जिससे नई सरकार पर निवेशकों का विश्वास और बाजार की उम्मीदें प्रकट हुई थी। इस सकारात्मक ऊर्जा की गति को बनाए रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। यह बहुत ही संतुष्टि के साथ अब कहा जा सकता है कि वित्त मंत्री का पहला बजट इस कठोर परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण रहा। जैसे ही वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण पूरा किया सेंसेक्स एवं बाजार ने एक उछाल के साथ उनका स्वागत किया।

बजट का स्वागत पूरे उत्साह से केवल सेंसेक्स ने ही नहीं बल्कि लगभग सभी आर्थिक विश्लेषकों ने किया। बजट ने न केवल अर्थव्यवस्था की तात्कालिक चिंताओं को ही दूर किया बल्कि भारत को आने वाले वर्षों में सुदृढ़ एवं वैभवशाली बनाने की रणनीति का ब्लू प्रिंट भी सामने रखा है। एक तरफ जहां वित्त मंत्री ने वित्तीय घाटे को 4.1 प्रतिशत पर रखा है वहीं दूसरी ओर 2016-17 तक वित्तीय घाटे को 3 प्रतिशत तक पर लाने का इरादा व्यक्त किया है। वह भी तब जब उन्होंने आने वाले 3-4 वर्षों में विकास दर को 7-8 प्रतिशत तक ले जाने की बात कही है। बजट का पूरा जोर मुद्रास्फीति घटाने, वित्तीय अनुशासन बनाने, रोजगार पैदा करने, कौशल विकास तथा पूरा आर्थिक परिदृश्य को सुधारने पर रहा है जिससे उच्च विकास दर को प्राप्त किया जा सके। नये आईआईटी, आईआईएम, एम्स, मणिपुर में राष्ट्रीय खेल-कूद विश्वविद्यालय की स्थापना से युवाओं की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। इसके साथ ही निर्माण, उत्पादन, आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्र पर जोर देने से रोजगार बढ़ेगा तथा अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इनके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, श्याम प्रसाद मुकर्जी रूरबेन मिशन, पं. मदन मोहन मालवीय शिक्षण कार्यक्रम तथा जय प्रकाश नारायण सेन्टर फॉर एक्सीलेंस इन ह्यूमनिटीज तथा गंगा नदी के लिए विशाल आवंटन जैसे कदम बजट के प्रमुख आकर्षण हैं। उत्तरी-पूर्व राज्यों एवं जम्मू कश्मीर पर विशेष बल

इन क्षेत्रों की आर्थिक दशा एवं दिशा को नए आयाम देगी।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि बजट को बहुत कम समय में तैयार किया गया। वित्त मंत्री को इसके लिए बधाई देना चाहिए कि मात्र 45 दिनों की कड़ी मेहनत में उन्होंने देश के हर वर्ग के अपेक्षाओं का ध्यान रखा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है चुनाव घोषणापत्र को विभिन्न पहलों एवं योजनाओं के माध्यम से बजट में पूरा करने का प्रयास किया गया है। यह वास्तव में 'सबका साथ, सबका विकास' का मंत्र वाक्य जो भाजपा के घोषणापत्र में है, को पूरा करने की ईमानदार कोशिश है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ठीक ही कहा है कि यह बजट लोगों की आशाओं एवं अपेक्षाओं को विश्वास में बदलने वाला बजट है। बजट ने 'अच्छे दिन' की दिशा में कम बढ़ा दिए हैं और यदि इसे प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया गया तो इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले वर्षो में भारत एक सुदृढ़, समृद्ध एवं वैभवशाली देश के रूप में उभरेगा। ■

नए राज्यपालों की नियुक्ति

संवाददाता द्वारा

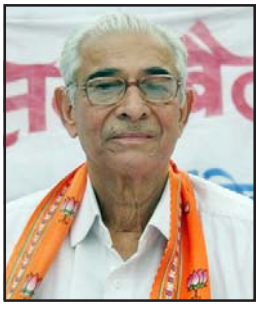

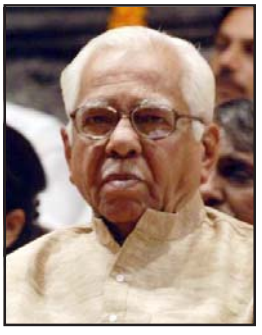

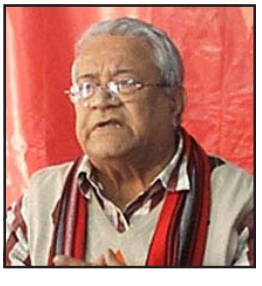

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 14 जुलाई 2014 को पांच नए राज्यपालों की नियुक्ति की। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राम नाइक को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री ओमप्रकाश कोहली को गुजरात का राज्यपाल बनाया गया।

राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान के मुताबिक नाइक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद संभालेंगे। वे श्री बीएल जोशी की जगह लेंगे।

तीन बार सांसद रहे 80 साल के श्री नाइक को एकमात्र ऐसे मंत्री होने का गौरव प्राप्त है जिन्होंने एक ही सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के तौर पर पांच साल का कार्यकाल पूरा किया।

साल 1994 से 2000 तक राज्यसभा के सदस्य रहे श्री ओम प्रकाश कोहली गुजरात के राज्यपाल होंगे। वे कमला बेनीवाल की जगह लेंगे जिन्हें इस साल नवंबर तक उनके शेष कार्यकाल के लिए सरकार ने मिजोरम का राज्यपाल बनाकर भेजा है। साल 2009 में भाजपा की दिल्ली प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रहे कोहली विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े रहे हैं। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष थे। बाद में वे दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के प्रमुख भी रहे।

उत्तर प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री केशरीनाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल होंगे। यह पद श्री एमके नारायणन के इस्तीफे के बाद खाली हुआ है। श्री त्रिपाठी इस साल नवंबर में 80 साल के हो जाएंगे। वे पांच बार विधायक रहे हैं।

साल 1951 में जनसंघ की स्थापना के समय से पार्टी के सदस्य रहे 87 साल के श्री बलराम दास टंडन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया। वे श्री शेखर दत्त की जगह लेंगे जिन्होंने 18 जून को इस्तीफा दिया था।

श्री टंडन 1969 में पंजाब के उप मुख्यमंत्री थे। वे प्रकाश सिंह बादल की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। भाजपा के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर कार्यसमूह के सदस्य और भाजपा के प्रवासी मित्र संगठन के सह-संयोजक पद्मनाभ आचार्य को नगालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

राष्ट्रपति ने आचार्य से नियमित व्यवस्था होने तक त्रिपुरा के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी भी संभालने को कहा है। ■

अमित शाह बने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष

गत 9 जुलाई 2014 को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने पार्टी के नए अध्यक्ष के नाते श्री अमित शाह के नाम की घोषणा की। अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आज से और अभी से श्री अमित शाह भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शाह को मिठाई खिलाकर बधाई दी। श्री राजनाथ सिंह ने श्री अमित शाह को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी को उत्तर प्रदेश में असाधारण सफलता मिली। उनमें गजब की काल्पनिक क्षमता है और वे प्रबंधन में माहिर हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष के नाते श्री अमित शाह का नाम तय हुआ। श्री शाह के भाजपा अध्यक्ष बनते ही देशभर में स्थित पार्टी कार्यालयों में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया।

भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह का जीवन वृत्त

अप्रतिम संगठनात्मक क्षमता के धनी और कुशल रणनीतिकार श्री अमित शाह, जमीन से जुड़े एक ऐसे नेता हैं, जिनका एक प्रतिष्ठित राजनीतिक रिकॉर्ड और वह अपने आदर्शों के लिए प्रतिबद्धता के साथ जुड़े हैं।

22 अक्टूबर 1964 को जन्मे श्री अमित शाह के परिवार में पहले कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं था, इसके बजाय, उनके परिवार में मानव प्रेम की वो भावना थी जिसने श्री अमित शाह के अंदर समाज की सेवा करने की इच्छा को जगाया। 14 वर्ष की छोटी सी उम्र में, श्री अमित शाह ने एक 'तरुण स्वयंसेवक' के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। इस निर्णय ने उनके जीवन की दिशा बदल दी।

गुजरात भाजपा में संगठनात्मक भूमिका:

1982 में जैव रसायन विज्ञान के एक छात्र के रूप में, उन्होंने अहमदाबाद में छात्रों के संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सचिव की जिम्मेदारी ली। बाद में वे भाजपा के अहमदाबाद शहर इकाई के सचिव बने। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्री अमित शाह भाजपा की गुजरात इकाई में कई महत्वपूर्ण पदों को सम्हाला और वहाँ के प्रतिष्ठित नेता बनकर उभरे। 1997 में वे भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बने और बाद में भाजपा की गुजरात इकाई के उपाध्यक्ष बने।

अभूतपूर्व चुनावी उपलब्धियाँ:

1995 में श्री अमित शाह पहली बार सरखेज विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में चुने गए। वह 1998 में इसी निर्वाचन क्षेत्र से पुन: निर्वाचित किए गए। इस बार उन्होंने अपने प्रतिद्वन्द्वी को 1,32,477 मतों के अंतर से हराया। 2002 में उन्होंने एक तरह का रिकार्ड बनाया जब वे अपने प्रतिद्वन्द्वियों को 1,58,036 वोटों से हराकर सरखेज विधानसभा क्षेत्र से पुन: निर्वाचित किए गए। वर्ष 2007 में उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस बार उन्होंने 2,32,823 वोट के अंतर से जीत दर्ज की। 2012 में वह नरनपुरा निर्वाचन क्षेत्र से पांचवीं बार गुजरात विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए।

सहकारी क्षेत्र की कायापलट:

हर मृतप्राय इकाई को इसकी नियति बदलने के लिए एक दूरदर्शी नेता की जरूरत पड़ती है। अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के लिए यह सच है, जो वर्ष 2000 में दिवालिया होने के कगार पर था और नेतृत्व की कमी के कारण एक कमजोर बैंक घोषित कर दिया गया था। यह वह समय था जब श्री अमित शाह को इस चुनौती का सामना करने के लिए बैंक के अध्यक्ष के रूप में लाया गया था। शाह ने नैतिक मूल्यों के साथ एक सकारात्मक शुरूआत की और माना कि सक्षम प्रशासन के साथ लाभांश का भुगतान, नैतिकता और लग कर काम करने से बैंक के अच्छे दिन वापस लौट सकते हैं। जिस वर्ष वह बैंक के अध्यक्ष बने उस वर्ष बैंक ने 20.28 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया था। उनके

पदभार संभालने के एक वर्ष के अंदर ही बैंक ने अपने सारे कर्जे चुका दिए और 10 प्रतिशत लाभांश की घोषणा के साथ, अन्य लाभ कमाने वाले बैंकों की श्रेणी में शामिल हो गया। आज, अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक लिमिटेड देश के 367 सहकारी बैंकों में से एक प्रमुख बैंक बन गया है।

माधवपुरा और अन्य शहरी सहकारी बैंकों के बंद होने से जब लोगों का विश्वास सहकारी बैंकों से उठ गया था, तब श्री शाह ने जमाकर्ताओं का विश्वास फिर से पाने की जिम्मेदारी स्वयं ली। उनकी देखादेखी ही सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने माधवपुरा बैंक के लिए एक पुनर्निर्माण पैकेज को शुरू किया। श्री शाह ने स्वयं ही फ्लेक्सी जमा योजना की शुरूआत सुनिश्चित करके सहकारी बैंकों को लाभ के लिए अपने धन का निवेश करने के लिए सक्षम बनाने का कार्य किया। श्री शाह के जोर देने पर राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंकों के कानून को संशोधित किया गया। कानून अब दोषी सहकारी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कर सकता है।

राज्य प्रशासन में उल्लेखनीय सफलता:

1995 में, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री केशुभाई पटेल के कार्यकाल के दौरान, अमित शाह सबसे कम उम्र के गुजरात राज्य वित्तीय निगम (GSFC) के अध्यक्ष बने। 2002 में, श्री अमित शाह नरेंद्र मोदी सरकार में राज्य मंत्री बने। मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने परिवहन, पुलिस, आवास, सीमा सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा, ग्राम रक्षक दल, होमगार्ड, जेल, निषेध, आबकारी, कानून और न्याय, संसदीय कार्य और प्रतिष्ठित गृह मंत्रालय सहित कई विभागों का कार्यभार संभाला।

चुनाव प्रबंधन में महारत:

राजनीतिक रणनीति और दृष्टिकोण में अपने कौशल के कारण वे 2010 में पार्टी के महासचिव के रूप में नियुक्त किए गए और बाद में उन्हें चुनावी रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का राज्य का प्रभारी बनाया गया। एक छोटी सी अवधि के अंदर ही श्री शाह ने उत्तर प्रदेश में भाजपा के भाग्य को पलट दिया और भाजपा और उसके सहयोगियों को 80 लोकसभा सीटों में से 73 पर जीत हासिल हुई, जो अब तक का सबसे शानदार परिणाम था। उनके दो साल से भी कम समय में उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में काम करते हुए भाजपा के वोट प्रतिशत में कम से कम ढाई गुना वृद्धि हुई है। याद रहे कि श्री शाह इसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी तथा वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के चुनावों का भी प्रबंधन कर चुके हैं और उनकी चुनावी जीत सुनिश्चित कर चुके हैं।

श्री शाह भाजपा की चुनाव समिति के सदस्य भी थे, और 2014 में, जनसंपर्क, सामूहिक अभियान और नए मतदाताओं के नामांकन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर, एक परिणामोन्मुख रणनीति बनाई और 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को अभूतपूर्व विजय दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

खेल प्रशासन:

श्री शाह ने गुजरात राज्य के शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। 2009 में वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने और 2014 तक इसके अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने तक वह इस पद पर रहे। ■

प्रधानमंत्री द्वारा अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हार्दिक बधाई

गत 9 जुलाई को जारी एक संदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री अमित शाह को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने पर बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पार्टी उनके नेतृत्व में मजबूत होती चली जाएगी।

प्रधानमंत्री के ट्वीट पर लिखे उनके संदेश का पाठ इस प्रकार है:

''भाजपा अध्यक्ष चुने जाने पर श्री अमित शाह को ढेरों शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में निश्चित ही पार्टी का विस्तार होगा, पार्टी और मजबूत बनेगी।''

अमित भाई ने एक साधारण कार्यकर्ता के रूप अपनी यात्रा का आरम्भ किया और अपने अथक कठोर परिश्रम और दृढ़संकल्प से उन्होंने बार-बार स्वयं को सफल सिद्ध किया।

मैं विशेष रूप से राजनाथ जी का उनके महान नेतृत्व के लिए विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं जिसके कारण पार्टी ने सफलता की नई ऊंचाईयाँ छुई हैं।

पार्टी नेताओं के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के नि:स्वार्थ प्रयासों से भाजपा का भारत को और भी अधिक मजबूत और विकास करने का मिशन जारी रहेगा।'' ■

आम बजट 2014–15

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 10 जुलाई 2014 को संसद में आम बजट प्रस्तुत किया। प्रस्तुत है इस बजट के प्रमुख बिन्दुः

1. हाल के वर्षों का सबसे विस्तृत बजट :

- बजट में लगभग सभी मुद्दों को शामिल किया गया है।
- **मंगल और अल्पसंख्यक :** बजट में अगर मंगल मिशन की बात की गई तो इसमें अल्पसंख्यकों के बारे में भी सोचा गया है। बजट में अल्पसंख्यकों के परम्परागत कौशल के उन्नयन और मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है।
- **पूंजी बाजार और ग्रामीण बाजार :** बजट में अगर पूंजी में सुधार की चर्चा है तो इसमें ग्रामीण और कृषि बाजारों की भी चिंता की गई है। किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिले इसके लिए बजट में एक राष्ट्रीय बाजार विकसित करने और मूल्य स्थरीकरण कोष बनाने का प्रस्ताव है।
- **शहरी और ग्रामीण विकास :** बजट में अगर 100 स्मार्ट शहर विकसित कर शहरी इलाकों के बारे में चिंता व्यक्त की गई है तो इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन, सभी के लिए 2022 तक घर, सस्ते मकान और मलिन बस्ती विकास पर भी ध्यान दिया गया है।
- बजट में यदि शहरी इलाकों में युवा आईटी की शुरुआत करने का प्रस्ताव है तो इसमें शुरुआती ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम (अनुसूचित जाति के समुदाय से शुरुआत, सूक्ष्म, मझौले और मध्यम (एमएसएमई) उद्यम क्षेत्र में पूंजी को आकर्षित करने के लिए 10000 करोड़ क्षेत्र में पूंजी को रुपये का प्रस्ताव है।

1. किसानों के लिए घोषणाएं :

- भूमिहीन किसान : गारंटी नहीं होने के कारण भूमिहीन किसानों को संस्थानों से वित्तीय मदद नहीं मिल पाती है। किसानों को साहूकारों से बचाने के लिए इस बार बजट में नाबार्ड के जरिये उन्हें वित्तीय मदद देने का प्रस्ताव किया गया है।
- किसान टेलीविजन
- किसानों को ब्याज पर सब्सिडी : समय पर ऋण का भुगतान करने पर किसानों को प्रोत्साहन के रुप में ब्याज पर 3 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
- कृषि भंडारगृह बुनियादी ढांचा कोष : कृषि उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए 5000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
- दीर्घकालिक ग्रामीण ऋण कोष : कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में उपयोगी सृजन के लिए 5000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
- उत्पादक विकास और उन्नयन राशि: छोटे और सीमांत किसानों के लिए 200 करोड़ रुपये।

2. कलाकारों और अकुशल कामगारों के लिए :

- कुशल भारत : वैल्डरों, बढ़ई, मोची, राज कुशल भारत गीर, लुहारों और बुनकरों आदि पेशे से जुड़े लोगों के कौशल विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण और प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि वे सम्मानित जीवन बिता सकें।
- टेक्सटाइल क्लस्टर : हस्तकला अकादमी और पश्मीना संवर्द्धन कार्यक्रम आम आदमी के प्रति इस सरकार की चिंता को उजागर करते हैं।

3. ग्रामीण विकास :

- महात्मा गांधी नरेगा : इसका इस्तेमाल अधिक लाभकारी चीजों के लिए जिनका सम्बन्ध कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों से है।
- राष्ट्रीय आजीविका मिशन: इसका 100 और जिलों में विस्तार:
- ग्रामीण आवास योजना: आवंटन बढ़ाकर 8000 करोड़ रुपये।
- नीरआंचल वाटरशैड विकास कार्यक्रम।
- पीने का सुरक्षित पानी।

4. स्वास्थ्य और शिक्षा

- आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, विदर्भ और पूर्वांचल में 4 नये एम्स
- 12 नये सरकारी मेडिकल कॉलेज
- मुफ्त दवा सेवा और मुफ्त रोग निदान सेवा
- बुजुर्गों के लिए 2 राष्ट्रीय संस्थान
- 5 नये आईआईटी और 5 नये आईआईएम स्थापित किए जाएंगे
- वर्चुअल कक्षाएं स्थापित करने और ऑनलाईन पाठ्यक्रमों

के लिए 100 करोड़ रुपये।

5. समाज के सभी वर्गों की हिफाजत :

- महिला और बाल विकास: निर्भय निधि काम में लाई जाएगी तथा संकट प्रबंधन केन्द्रों की स्थापना। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना। स्त्री पुरुष भेदभाव दूर करने के लिए स्कूलों के पाठ्यक्रम में विशेष अध्याय शामिल किए जाएंगे।
- अनुसूचित जाति।
- अनुसूचित जनजाति : वन बंधु कल्याण योजना।
- वरिष्ठ नागरिक : वरिष्ठ नागरिकों के लिए आय कर में छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये।
- शारीरिक रुप से अक्षम व्यक्ति: सहायक उपकरण खरीदने के लिए सहायता। सामान्य संयुक्त डिजाइन और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना। शारीरिक रुप से अक्षम लोगों के खेलने के लिए केन्द्र की स्थापना।
- नेत्रहीनों के लिए : करेंसी नोटों पर 15 नये ब्रेल प्रेस और ब्रेल संकेत।

6. आम आदमी के हित में कर प्रस्ताव :

- व्यक्तिगत आय कर छूट की सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये की गई।
- धारा 80सी के अंतर्गत निवेश की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये की गई। इससे दीर्घकालिक बचत में घरेलू निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- आवास ऋण पर ब्याज पर मिलने वाली छूट की सीमा डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है।
- अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के कारण टेलीविजन, कम्प्यूटर, जूते चप्पल और साबुन सस्ते हो जाएंगे और सिगरेट, पान मसाला, तम्बाकू, शीतल पेय तथा हीरा मंहगा हो जाएगा। इससे एक बार फिर यह साबित होता है कि बजट आम आदमी के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।■

दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने सतीश उपाध्याय

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने 8 जुलाई 2014 को दक्षिण दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय को दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोनीत किया।

श्री उपाध्याय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् में अनेक दायित्वों को निभा चुके हैं एवं दिल्ली प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ■

विहिप नेता आचार्य गिरिराज किशोर नहीं रहे

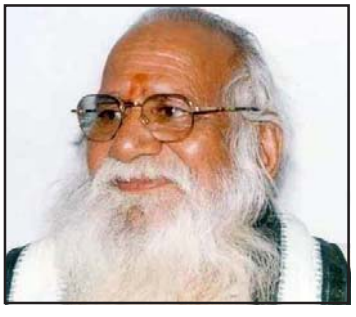

विश्व हिन्दू परिषद के वरिष्ठ नेता आचार्य गिरिराज किशोर का 96 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने जीवनभर देश, धर्म और समाज की सेवा करते हुए संसार से विदा ली।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का शोक संदेश

विश्व हिन्दू परिषद के मार्गदर्शक आचार्य गिरिराज किशोर के निधन का समाचार सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। आचार्य गिरिराज किशोर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ और विश्व हिन्दू परिषद के माध्यम से अपने अंतिम समय तक देश और समाज की समर्पित भाव से सेवा की। शिक्षक के रूप में सार्वजनिक जीवन शुरु करने वाले आचार्य गिरिराज किशोर ने कुछ ही समय बाद नौकरी छोड़कर अपना जीवन भगवान श्रीराम के कार्यो के लिए समर्पित कर दिया। आपातकाल के दौरान उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने का संघर्ष किया और जेल गये। त्याग और निर्भीकता के प्रतीक आचार्य गिरिराज किशोर ने अपना शरीर भी सामाजिक कार्य के लिए दान देने का संकल्प लिया। उनका व्यक्तित्व सदैव ही देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। ■

हम दूर करेंगे निवेशकों का डर : अरुण जेटली

मोदी सरकार के पहले बजट को वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली हर वर्ग में भरोसा जगाने की एक शुरुआत करार देते हैं। आर्थिक सुधार, उद्योगों को प्रोत्साहन और जनता को राहत श्री जेटली की तीन सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। बजट सत्र के दौरान संसद परिसर में अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर उन्होंने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख नितिन प्रधान से खुलकर बातचीत की। पेश है ब्योरा-

- अभी तक योजना आयोग और दूसरे सलाहकार सरकार का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। क्या इससे कामकाज में दिक्कत नहीं आ रही?

ऐसे लोग जिनसे राय मशविरा किया जा सके, उनकी संख्या अधिक हो तो उससे मदद होती है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की तलाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार बनने के बाद पहला काम निश्चित समयावधि में बजट पेश करने का था। जो सुविधाएं उपलब्ध थीं उन्हीं में काम करना था। हमने यही किया भी। लेकिन सिस्टम में सलाह देने वाले लोग अधिक हों तो हमेशा बेहतर होता है।

- सरकार बनाने के बाद पहली बार अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर से रूबरू होने के बाद क्या प्रतिक्रिया थी?

देखिए, अर्थव्यवस्था की स्थिति हमसे छुपी नहीं है। आंकड़े भी हमारे लिए नए नहीं थे। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती निवेशकों के भरोसे को कायम करने की थी। घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेशक सरकार में भरोसा तलाश रहे थे। देश के कर प्रावधानों से उन्हें शिकायतें थीं। फैसला करने की रफ्तार बेहद धीमी थी। इसलिए जरूरी था कि यह भरोसा कायम किया जाए। बाधाएं दूर होंगी तो निवेशक भी निवेश करना शुरू करेंगे। इसलिए जरूरी है कि अर्थव्यवस्था को विकास के उस रास्ते पर लाया जाए, जिस पर हम चलना चाहते हैं। हमने विकास की रफ्तार तेज करने का एक रास्ता चुना है। इसलिए कदम भी उसी लिहाज से उठाने होंगे।

- क्या बजट में इस संबंध में पर्याप्त कदम उठाए गए हैं?

देखिए, कुछ फैसले बजट में लिए गए हैं। लेकिन कई फैसले ऐसे भी होते हैं जिन्हें सरकार बजट से इतर लेती है। सरकार बनने के बाद 45 दिनों के भीतर हमने जो भी फैसले लिए, उनमें इस बात का ध्यान रखा गया कि वे विकास की राह की हमारी सोच के मुताबिक लिए जाएं।

- विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस बजट में उठाए कई कदमों की आलोचना कर रही है?

मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता कि पिछली सरकार ने

क्या किया। अब हमें डिलीवर करना है। मैं ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहता, जिससे अर्थव्यवस्था को लेकर सेंटीमेंट खराब हों। हां, जो घोषणाएं हमने की हैं अथवा पिछली सरकार की जिन नीतियों को हमने जारी रखा है, मैं उन पर कायम हूं। चाहे वह राजकोषीय घाटे को चुनौतीपूर्ण 4.1 फीसद के लक्ष्य तक सीमित रखने की ही बात क्यों न हो। हमने उनके द्वारा तय लक्ष्य को बजट में शामिल किया है। मुझे भरोसा है कि हम उसे पूरा कर पाएंगे। हां, जहां तक बजट घोषणाओं की आलोचना करने की बात है, तो वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर वे सोचते है कि हम उन्हीं की नीतियों-विचारों पर चल रहे हैं तो उन्हें दोनों सदनों में बजट का समर्थन करना चाहिए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इतना कम समय मिलने के बावजूद हमने काफी गड़बड़ियों को दूर किया है। हमने इस बजट में कई उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाया है।

- मसलन..?

कर ढांचा इनमें से एक है। पिछली सरकार की कर नीतियों ने निवेशकों को भयभीत कर रखा था। निवेशकों के इस डर को दूर करने के लिए हमने इस बजट में मुख्यत: चार कदम उठाए हैं।

पहला, पुरानी तारीख से लागू होने वाले करों में बदलाव का संसद का अधिकार खत्म करना। दूसरा, घरेलू निवेशकों के लिए एडवांस रूलिंग मैकेनिज्म तैयार करना ताकि वे निवेश से पूर्व ही फैसले ले सकें। तीसरा, ट्रांसफर प्राइसिंग के मामलों में विवाद खत्म करने की कोशिश। और चौथा, उद्योग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के बीच परामर्श का तंत्र विकसित करना ताकि किसी भी विवाद को वैधानिक हल की स्थिति तक ले जाया जा सके।

- अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए किन कदमों को महत्वपूर्ण मानते हैं?

मेरी लगातार कोशिश मैन्यूफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने की रही है। सरकार बनने के बाद और बजट से पहले मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र को मिल रही उत्पाद शुल्क संबंधी कुछ राहतों को हमने आगे भी बनाए रखने का फैसला किया। बजट में इनका दायरा और बढ़ाया। विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए हमारा मुख्य जोर मैन्यूफैक्चरिंग पर ही है। इसके लिए एमएसएमई क्षेत्र पर खासा ध्यान दिया गया है। इस क्षेत्र में निवेश की सीमा कम की गई है। बिजली क्षेत्र के लिए कई कदम उठाए हैं। कई प्रमुख क्षेत्रों के लिए शुल्क ढांचे में बदलाव किया है।

- सिर्फ रक्षा और बीमा में ही एफडीआइ क्यों?

रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में 49 फीसद एफडीआइ की नीति मील का पत्थर साबित होगी। यह कदम लंबी अवधि में देश को फायदा पहुंचाएगा। रक्षा उत्पादन में एफडीआइ खोलने को लेकर दो सवाल उठते हैं। पहला, एफडीआइ क्यों मंजूर किया जाए? इसका सीधा सा जवाब है। अभी तक हम रक्षा क्षेत्र के लिए सभी उपकरण विदेश से खरीदते हैं। इसके लिए विदेशी कंपनियों पर ही निर्भर हैं। लेकिन अगर हम विदेशी कंपनियों को अपने यहां उत्पादन इकाई लगाने को प्रोत्साहित करते हैं तो हमें घरेलू स्तर पर ही ये उपकरण और कलपुर्जे उपलब्ध होंगे। इसलिए देश में ही रक्षा उत्पादन का हब तैयार करना बेहतर है।

दूसरा सवाल है कि 51 फीसद एफडीआइ क्यों नहीं। तो इसका जवाब है कि ऐसा करने से हम अपने उद्देश्यों को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में कंपनियों पर भारतीय नियंत्रण नहीं रहता। जैसे विदेशी कंपनी की इकाइयां कई अन्य देशों में हैं, एक इकाई भारत में भी होती। इससे हमें क्या लाभ होता? हालांकि इस संबंध में शुरुआती तौर पर सरकार से 49 फीसदी एफडीआइ को लेकर ही अधिक पूछताछ की गई।

- सुधारों को लेकर राजनीतिक स्वीकार्यता कितनी मायने रखती है?

मेरी राय में प्रत्येक सुधार राजनीतिक तौर पर स्वीकार्य होना चाहिए। भारत में तो इस तरह के कई कदम उठाए जाते हैं ताकि आप ऐसे मुद्दों पर टकराव की स्थिति से बच सकें। इसके अलावा भी हमने कई कदम उठाए हैं जिनके जरिये हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। अर्थव्यवस्था को एफडीआइ के लिए खोलने का फैसला निवेशकों को आकर्षित करेगा। बैंकों के पूंजीकरण के लिए उन्हें खुद पूंजी जुटाने का अधिकार बैंकों को मजबूत बनाएगा।

- जीएसटी लंबे समय से अटक रहा है। क्या निकट भविष्य में यह लागू हो पाएगा?

देखिए, इसे लागू करना है तो राज्यों के हितों को ध्यान में रखना होगा। इसे जल्द से जल्द लागू करने के लिए

हम यही कर सकते हैं कि एक-दो उत्पादों को इसके दायरे से बाहर रख दें। अन्यथा सात साल फिर इंतजार करें।

- ब्याज दरों में निकट भविष्य में कमी की कितनी संभावनाएं हैं?

यह निर्भर करेगा महंगाई की दर की स्थिति पर। अगर महंगाई दर थोड़ी और नीचे आती है तो ब्याज की दरें भी कम हो सकती हैं।

- क्या भविष्य में आयकर दरों में कमी की संभावना है?

मेरी समझ में व्यक्तिगत करदाताओं को एकमुश्त इतनी रियायतें शायद ही कभी मिली हों। होम लोन के ब्याज पर छूट की सीमा बढ़ना, निवेश की सीमा में वृद्धि ऐसे उपाय हैं जो न सिर्फ लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि घरेलू निवेश के लिए भी अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। यह मेरी और प्रधानमंत्री की अवधारणा का ही नतीजा है। हमारा मानना है कि लोग ज्यादा बचत करेंगे तो खर्च के लिए भी अधिक धन उपलब्ध होगा।

- क्या आने वाले समय में विनिवेश की रफ्तार बढ़ाने संबंधी कदम देखे जा सकते हैं? खासतौर पर रणनीतिक बिक्री के रूप में?

देखिए, विनिवेश के मामले में हम फिलहाल पिछली सरकार की ही नीति पर चल रहे हैं। जो कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं और कुशल प्रबंधन में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, वे तो आर्थिक विकास में भागीदारी कर ही रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे उपक्रम भी हैं जिनकी हालत बेहद खराब है। जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता उसमें क्या हो सकता है। हां, जिन्हें ठीक किया जा सकता है उस दिशा में कोशिश जरूर होगी। ऐसे उपक्रमों की पहचान करेंगे।

- जीएएआर जैसे विवादित मुद्दों पर क्या रुख है?

अभी इस पर बहुत अधिक विचार नहीं हुआ है। इन मामलों पर अभी पुरानी सरकार की नीतियों को ही आगे बढ़ाया गया है। जब इस पर विचार करने का वक्त आएगा तभी आगे की रणनीति बनाएंगे।

- स्कीमों को आवंटित धन में क्या आगे बदलाव की गुंजाइश है?

इस देश में कांग्रेस ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है। कांग्रेस को बेहतर आइडिया आने चाहिए थे। स्कीम जब बनती है तो उसमें एक टोकन राशि आवंटित होती है। लेकिन जैसे-जैसे उस पर काम शुरू होता है राशि बढ़ती है। आगे भी ऐसा होगा। जिन नई स्कीमों में अभी आवंटित राशि कम लग रही है उनमें आगे चलने पर जरूरत के मुताबिक आवंटन होता जाएगा।

- बजट से पहले बार-बार कहा जा रहा था जनता कड़वी दवा पीने के लिए तैयार रहे। क्या है वह कड़वी दवा?

कड़वी दवा से यह अर्थ कतई नहीं लगाया जाना चाहिए कि ऊंची कर की दरें लागू कर दी जाएं। इसका यही मतलब है कि यूजर चार्ज अदा करना होगा। आप जिस सेवा का इस्तेमाल करेंगे उसका भुगतान आपको करना होगा।

- देश में सूखे की आशंका जताई जा रही है। क्या देश इसके लिए तैयार है?

सरकार इसे लेकर चिंतित है। जुलाई आधा बीत रहा है। हम बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास वैकल्पिक योजना तैयार है।

- आपके बजट भाषण में शायरी नहीं थी?

यह मेरा स्टाइल नहीं है कि जनता पर बजट के जरिये बोझ डाल दो और फिर उन पर शेर ओ शायरी सुनाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ■

भाजपा संसदीय बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव

भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने 9 जुलाई 2014 को भारत के गृहमंत्री एवं निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह को अपने कार्यकाल में पार्टी का कुशल नेतृत्व करने के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की। श्री राजनाथ सिंह ने एक अत्यंत संवेदनशील स्थिति में पार्टी का नेतृत्व संभाला था और वहां से पार्टी के संगठन को सुदृढ़ करते हुए विगत लोकसभा में पार्टी को सर्वकालीन, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए संसद में स्पष्ट बहुमत की स्थिति तक पहुंचाया, इस हेतु सभी सदस्यों ने उनकी प्रशंसा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री राजनाथ सिंह का कार्यकाल भाजपा के इतिहास का उच्चतम बिन्दु रहा तथा भारतीय राजनीति के इतिहास में एक युगांतर स्थापित करने वाला कालखण्ड रहा। श्री राजनाथ सिंह के प्रति आभार प्रकट करते हुए संसदीय बोर्ड के सदस्यों ने यह आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन का लाभ आगे भी पार्टी को मिलता रहेगा। ■

यह बजट देश को मजबूत आधार प्रदान करेगा : अमित शाह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की ओर से बजट 2014-15 पर 10 जुलाई, 2014 को जारी प्रेस वक्तव्य

यह मोदी सरकार का पहला बजट है। इसमें जनता की अपेक्षाओं को संतोष देने का प्रयास किया गया है। यह संतुलित बजट है। एक तरफ मध्यम वर्ग का ध्यान रखा गया है, वहीं दूसरी ओर ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाये गए हैं। मैं वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी को एक साहस भरे, विकासोन्मुखी और दूर की सोच वाले ऐतिहासिक बजट को पेश करने के लिए बधाई देता हूँ जहाँ 125 करोड़ भारतीयों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। हमारी सरकार ने भारत के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए रोड मैप तैयार किया है। यह बजट भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र में शामिल सभी मुद्दों को समाहित किए हुए है। यह बजट हमारे ध्येय वाक्य 'सबका साथ, सबका विकास' को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है।

कांग्रेस सरकार द्वारा हमें उत्तराधिकार में मिला है - खाली तिजोरी, कमरतोड़ महंगाई, कराहती अर्थव्यवस्था, विकास की भ्रामक अवस्था, एक बड़ा राजकोषीय घाटा, करंट अकाउंट घाटा और घोर निराशापूर्ण माहौल। उन्होंने सरकार का प्रयोग देश की आम जनता के हितों की कीमत पर कुछ सीमित लोगों की स्वार्थपूर्ति के लिए किया। जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों भारतीयों ने कांग्रेस के बुरे शासन व कुरीतियों के खिलाफ एकजुट होकर बदलाव के लिए वोट किया।

वित्त मंत्री जी ने भारत के पुनरुद्धार के लिए एक व्यापक कार्ययोजना प्रस्तुत की है। यह बजट अर्थव्यवस्था में आशा और विश्वास का फिर से संचार करेगा। साथ ही यह हमारे सपने 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' को साकार करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। भारत के समावेशी, पारदर्शी और minimum government, maximum governance वाले शासन के सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने के लिए यह बजट एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

उन्होंने एक ऐसे एक्शन प्लान को प्रस्तुत किया है - जो सभी की मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करता है, बुनियादी व सामाजिक ढ़ांचे को मजबूती प्रदान करने वाला है, ग्रामों के जीवन स्तर को बढ़ाने वाला है, उन्नत कृषि के विकास में सहायक है, सशक्त उत्पादन व्यवस्था वाला है, करोड़ों युवाओं को रोजगार प्रदान करने वाला है, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा प्रदान करने वाला है और समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाला है।

हमने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे निवेशकों व उद्यमियों का विश्वास फिर से बहाल हो सके। यही विश्वास आने वाले वर्षों में देश के विकास और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरिणा व तेज गति प्रदान करेगा।

विशेष रूप से यह आम जनता के लिए बेहद फायदेमंद होगा जो छोटे करदाता व वरिष्ठ नागरिक हैं, (अब लोग बुजुर्गों के इलाज, महिला विकास, बच्चों की शिक्षा पर और अधिक खर्च करने में सक्षम हो सकेंगे), कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की योजना को यह प्रोत्साहित करने वाला है। तम्बाकू, गुटका व कोल्ड ड्रिंक्स पर करवृद्धि की घोषणा का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। युद्ध स्मारक निर्माण की प्रतिबद्धता, एक रैंक - एक पेंशन व कश्मीरी विस्थापितों की पुनर्वास योजना के लिए यह राष्ट्र आभारी है।

आज जो कदम उठाये गए हैं वे निश्चित रूप से निवेशकों के भरोसे को बढ़ाएगा, बचत-निवेश साइकिल को जीवित करेगा जो इस वर्ष विकास दर को 5.5-5.9 % तक पहुँचाने में सहायक होगा, एवं आने वाले दो वर्षों में और अधिक वृद्धि दर को प्राप्त करेगा। कृषि विकास और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष जोर दिया गया है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भंडारगृहों की स्थापना, ग्रामीण सड़कों का विकास और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा।

आधारभूत संरचनाओं के विकास पर विशेष बल दिया गया है। कराधान परिवर्तन पारदर्शिता बढ़ाएगी जिससे निवेशकों के विश्वास को बहाल करने में सहायक होगा।

एक बार पुनः मुझे यह देखकर अत्यंत संतोष हो रहा है कि हमारी पार्टी की योजना पूरी स्पष्टता के साथ देश के भविष्य को प्रगतिपथ पर बढ़ाने वाली है, जिससे सभी भारतवासी लाभान्वित होंगे। इसमें किसी प्रकार का शक नहीं है कि यह भाषण स्नेहपूर्वक आने वाले कई दशकों तक याद किया जाएगा। एक बार फिर से मैं श्री अरुण जेटली जी को इस सकारात्मक व विकासोन्मुखी बजट के लिए बधाई देता हूँ। ■

यह बजट देश की शिक्षा पर देता है बल : स्मृति ईरानी

गत 10 जुलाई को जारी एक प्रेस वक्तव्य में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने केन्द्रीय बजट 2014-15 में ऐसे अनेक पहलुओं को दिखाया है जिससे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

मंत्री महोदय का विचार है कि-

बजट में विशेष ध्यान शिक्षा और दक्षता विकास पर दिया है। विशेष रूप से, उच्च शिक्षा के योजनागत बजट में 2014-15 में काफी वृद्धि की गई है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता क्षेत्र में भी यह वृद्धि पर्याप्त की गई है। समग्र रूप से एचआरडी मंत्रालय के (योजनागत और-गैर-योजनागत) बजट दोनों में ही उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा ता साक्षरता विभाग में कुल मिला कर 12.3 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिलती जिसमें 2013-14 के पुन: आकलन में 74,621 करोड़ रूपए से बढ़ा कर 83,771 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

बजट में विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया है, जो इस सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है।

बजट में इस बात का दृढ़ संकल्प है कि शेष एक लाख कन्या शौचालयों और स्कूलों में पेय जल की सुविधाएं दी जाएंगी जिससे पहले दौर में 100 लाख लड़कियों को लाभ पहुंचेगा। इससे न केवल लड़कियों को स्कूल में प्रवेश करने में मदद मिलेगी, बल्क वे स्कूलों को छोड़ कर जाने पर भी रोक लगाएगी। जब लड़कियों को स्कूलों को आवश्यक स्वच्छता सुविधाएं मिलेंगी तो वे अपने घर में इस प्रकार की सुविधाएं चाहेंगी

जिससे स्वच्छ भारत का निर्माण होगा।

बजट में घोषित 'बेटी बचाओ योजना' से न केवल लड़कियों के मामले में विपरीत अनुपात में कमी आएगी बल्कि लड़कियों के लिए शिक्षा भी सुनिश्चित हो जाएगी।

बजट में लड़कियों को भी मुख्य धारा में लाने पर बल दिया गया है। स्कूल की पाठ्यचर्या में लड़कियों को मुख्य धारा के लाने के लिए अलग से एक अध्याय रखने का प्रावधान किया गया है। इससे लड़कियों, अध्यापकों और पूरे समुदाय में संवेदनशीलता का संचार होगा और समग्र रूप से लड़कियों और महिलाओं की इस संवेदनशीलता से हमारा समाज कहीं अधिक सद्भाव रखने को बढ़ावा देगा। इससे देश की सभी लड़कियों को लाभ होगा।

बजट में पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे सरकार उन विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान कर सकेगी जो हमारे व्यावसायिक कॉलेजों में अध्यापक बनना चाहते हैं। इससे अध्यापकों की उत्कृष्टता में सुधार आएगा और अन्तत: इससे हमारी स्कूल प्रणाली में विद्यार्थियों के शिक्षा परिणाम भी बेहतर बन पाएंगे। इनसे अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले लगभग 20,000 अध्यापक प्रशिक्षुओं को लाभ मिलेगा।

बजट में मदरसा आधुनिकीकरण का प्रावधान है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन रखा गया है। मदरसा आधुनिकीकरण से 10 लाख मुस्लिम बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिलेगी जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) से प्रमाणित होगी। इससे मुस्लिम विद्यार्थियों को अपनी मर्जी की उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति प्राप्त होगी।

बजट में स्कूल एसेसमेंट प्रोग्राम के लिए 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। विभिन्न पैरामीटरों के माध्यम से स्कूल की क्वालिटी का आकलन किया जा सकेगा, जैसे विद्यार्थी शिक्षा परिणाम, अध्यापकों द्वारा शिक्षा देने की उत्कृष्टता आदि, और ऐसे स्कूलों की पर्फोमेंस के सार्वजनिक डिस्पले से विद्यार्थियों के माता-पिता स्कूलों के बारे में और बेहतर चयन कर सकेंगे। इससे अन्तत: सभी बच्चों, माता-पिता और स्टेकहोल्डरों को लाभ मिलेगा।

बजट में 15 ब्रेल प्रेसों को निर्धारित करने के लिए राज्यों को सहायता देने की घोषणा की है। इससे ब्रेल पुस्तकों

का प्रकाशन हो सकेगा जिससे हमारे चक्षु दोषी विद्यार्थियों की सहायता मिल सकेगी।

बजट में एसएसए के लिए 28,635 करोड़ रुपए और आरएसएसए के लिए 4,966 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इससे देश में प्रारम्भिक और सेकेण्डरी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और स्कूल की शिक्षा की उत्कृष्टता में सुधार आएगा और स्कूलों के लगभग 23 करोड़ बच्चों को लाभ मिलेगा।

बजट में उत्तराखण्ड में 5 आईआईटी, 5 आईआईएम और नेशनल सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज की स्थापना की घोषणा स्वागत-योग्य कदम है। नए आईआईटी जम्मू, छत्तीसगढ़, केरल, गोवा और आंध्र प्रदेश में खोले जाएंगे। नए आईआईएम की स्थापना हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र और ओडिशा में की जाएगी। बजट में नए आईआईटी और आईएमएम के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में वर्चुअल क्लासरूम और मास्सिव ओपन ऑन लाइन, पाठ्यक्रमों की स्थापना की योजना है जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। एक राष्ट्रीय ई-लाइब्रेरी का निर्माण होगा जो सभी शैक्षिक संसाधनों के लिए संग्रह-स्थल रहेगी।

बजट में मध्य प्रदेश में स्थापित करने के लिए लोक नायक जय प्रकाश नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ह्यूमिनीटीज का प्रस्ताव है जो अपने किस्म की एक अलग योजना है।

मंत्री महोदय का विचार है कि बजट राशि घोषणाओं से सरकार की विकासात्मक रणनीति और 'सबका साथ सबका विकास' का जनादेश की झलक मिलती है। ■

केन्द्रीय बजट में हर वर्ग को मिली है राहत : राजनाथ सिंह

वित्तमंत्री श्री अरूण जेटली ने 10 जुलाई को केन्द्रीय बजट 2014-15 का बजट पेश कर लोगों की आशाओं और महत्वाकांक्षाओं का समाधान करने सफलता प्राप्त की है। इस बजट से 'नए जीवंत भारत' का रोड़मैप तैयार हुआ है।

इस केन्द्रीय बजट में परिवर्तन लाने की जो भूख लोगों में थी, उसकी पूर्ति करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की सच्ची संभावनाओं को प्राप्त करने का एक ढांचा खड़ा किया है। राजकोषीय मजबूती और आर्थिक पुन: बहाली प्राप्त करने केन्द्रीय बजट में स्पष्ट संकेत मिलता है और इस बारे में कई ठोस घोषणाएं की गई हैं।

गत 10 जुलाई को गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा केन्द्रीय बजट पर जारी वक्तव्य।

बजट में घोषित 'स्किल इण्डिया' (दक्ष भारत) जैसी योजनाओं से भारत के युवाओं का विश्वास ऊंचा उठेगा और देश में विशाल स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

'प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना' वर्षा-रहित क्षेत्रों में सिंचाई करने से न केवल किसानों को लाभ मिलेगा बल्कि इससे हमारी खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी।

बजट में विस्थापित काश्मीर आप्रवासियों के लिए 500 करोड़ रुपए का आबंटन किया है जिससे जम्मू और काश्मीर में राहत और पुनर्वास में तेजी लाने में मद मिलेगी।

बजट में पुलिस आधुनिकीकरण के लिए नियत 3000 करोड़ रुपए से हमारी सरकार के इस दृढ़ संकल्प का पता चलता है कि वह देश में वर्तमान पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहती है।

बजट में आयकर छूट भी वर्तमान 2 लाख से 250 लाख बढ़ाने के प्रस्ताव से वेतनभोगी वर्ग को बहुत कुछ राहत मिलेगी।

केन्द्रीय बजट में छह 'टेक्सटाइल क्लस्टर' का प्रस्ताव भारतीय टेक्सटाइल उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा और साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा करगा। बजट में गंगा उद्धार और गंगा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में धनकोष आबंटन करना भी सचमुच एक स्वागत योग्य कदम है।

बजट में समाज के लगभग सभी वर्गों के लिए अच्छी खबरें हैं, चाहे वे किसान हों, युवा हों, व्यापारी हों, उद्योगपति हों, मजदूर हों, महिलाएं हों, एससी-एसटी हों या फिर विकलांग लोग हों। ■

छोटा किंतु सधा कदम

प्रो. पुष्पेश पंत

कल तक जो लोग यह बहाना बनाते नहीं थकते थे कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे वह चरमराती अर्थव्यवस्था को तत्काल सुधार सकें, वे इस घड़ी मोदी-जेटली के बजट की आलोचना करते हुए यह शोर मचा रहे हैं कि इस बजट में नया कुछ नहीं और न ही कोई ऐसा बड़ा साहसिक कदम है जो देश को आर्थिक संकट के भंवर से निकाल सकता है। ईमानदारी का तकाजा यह है कि इस बजट का मूल्यांकन राजनीतिक दलगत पक्षधरता से हट कर किया जाए।

सबसे पहले यह याद रखने की जरूरत है कि जाते-जाते संप्रग-कांग्रेस सरकार चुनाव के पहले अंतरिम बजट पेश कर चुकी थी और उसके बाद नई सरकार के वित्त मंत्री के हाथ कोई अप्रत्याशित पहल करने के लिए बंधे हुए थे। आय और खर्च का जो आवंटन पूर्ववर्ती कर गए उसमें छेड़छाड़ की गुंजायश नहीं थी। दूसरी बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि कमजोर मानसून की आशंका तथा इराक और सीरिया के संकट के कारण अगले कुछ महीनों में असाधारण रूप से सतर्क रहने की अनिवार्यता, जिसे नकारना आत्मघातक ही हो सकता है।

हमारी राय में इस बजट की सबसे बड़ी उपलब्धि देश में आत्मविश्वास और नई आशा का संचार है। इस सरकार ने आरंभ से ही यह स्पष्ट कर दिया है कि उसमें राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव नहीं। राष्ट्रहित में कड़े और कड़वे फैसले लेने से वह हिचकेगी नहीं। मोदी खुद यह कह चुके हैं कि कुछ समय के लिए लोकप्रियता गंवाने से वह हिचकिचाएंगे नहीं। यह समय कमर कसने का है। जो फर्क संप्रग और कांग्रेस के जमाने से है, वह यह है कि आज आम आदमी को भरोसा है कि कमर कसने को सिर्फ कमजोर नागरिक से ही नहीं कहा जा रहा है। जब तक हालात सुधरते नहीं, कष्ट सभी को समान रूप से झेलना पड़ेगा। लोकलुभावन परियोजनाओं का एलान कर सरकारी खजाने को भ्रष्टाचारी तरीके से लुटाने की और इससे वोट जुटाने की कांग्रेसी रणनीति के दर्शन इस बजट में नहीं होना संतोष का विषय है। यह बात जाने कितनी बार दोहराई जा चुकी है कि यह सरकार पूंजीपतियों की हिमायती है, यह गरीबों का गला काटती रहेगी और उनके पेट पर लात मारेगी। ऐसे सभी भविष्य वक्ताओं को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने निराश किया है। इस बजट में समाज के हर तबके के लिए कुछ न कुछ राहत है और कुछ न कुछ बेहतरी की संभावना। सीमावर्ती प्रदेश हों, अल्पसंख्यक या फिर आधारभूत ढांचे में सुधार से आर्थिक विकास की दर तेज करके रोजगार पैदा करने का संकल्प।

सबसे बड़ी बात यह है कि मनमोहन सिंह की लकवाग्रस्त सरकार के दौर के बाद बिना समय गंवाए नीति निर्धारण तथा सुशासन के लिए तत्पर इस राजग सरकार की विश्वसनीयता में किसी को अब तक शक करने की वजह नहीं मिली है। मोदी की और उनके सहयोगियों की कथनी और करनी के बीच वैसी कोई खाई नजर नहीं आती जैसी संप्रग के कार्यकाल में हमारा जीवन दूभर करती रही थीं। इसी कारण जनता धीरज धरने को तैयार है। वह यह जानती है कि सरकार के गठन के मात्र पैंतालीस दिन बाद प्रस्तुत यह बजट एक छोटा सा पहला कदम है एक लंबे सफर की शुरूआत का! आवश्यकता इस बात की है कि सरकार की इच्छाशक्ति को जिम्मेदार नागरिकों का मनोबल भरपूर समर्थन दे।■

(लेखक स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू में प्रोफेसर हैं।)

(साभार : दै. जागरण)

हमारी राय में इस बजट की सबसे बड़ी उपलब्धि देश में आत्मविश्वास और नई आशा का संचार है। इस सरकार ने आरंभ से ही यह स्पष्ट कर दिया है कि उसमें राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव नहीं। राष्ट्रहित में कड़े और कड़वे फैसले लेने से वह हिचकेगी नहीं। मोदी खुद यह कह चुके हैं कि कुछ समय के लिए लोकप्रियता गंवाने से वह हिचकिचाएंगे नहीं। यह समय कमर कसने का है। जो फर्क संप्रग और कांग्रेस के जमाने से है, वह यह है कि आज आम आदमी को भरोसा है कि कमर कसने को सिर्फ कमजोर नागरिक से ही नहीं कहा जा रहा है। जब तक हालात सुधरते नहीं, कष्ट सभी को समान रूप से झेलना पड़ेगा। लोकलुभावन परियोजनाओं का एलान कर सरकारी खजाने को भ्रष्टाचारी तरीके से लुटाने की और इससे वोट जुटाने की कांग्रेसी रणनीति के दर्शन इस बजट में नहीं होना संतोष का विषय है।

रेल बजट : प्रमुख बिंदु

- 11 रेलगाड़ियों का संचालन विस्तारित।
- विशेष उत्सव रेलगाड़ियां जारी रहेंगी।
- खामियों को दूर करने के लिए तैयार।
- पूर्वोत्तर में 23 परियोजनाओं पर काम जारी। 2014-15 में इसके लिए 5,116 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो एक साल पहले के मुकाबले 54 फीसदी अधिक है।
- समर्पित माल ढुलाई गलियारे पर बराबर नजर रखी जाएगी।
- जम्मू एवं कश्मीर में बनिहाल-कटरा लिंक पर काम शुरू किया जाएगा। इस बीच एक ही टिकट पर श्रीनगर तक की यात्रा के लिए एक बस प्रणाली शुरू की गई है।
- कुछ रेलगाड़ियों और कुछ स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा।
- पांच साल में पेपरलेस रेल कार्यालय।
- तेज रफ्तार रेलगाड़ियों के लिए हीरक चतुर्भुज। इसके लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित।
- चुनिंदा मार्गों पर रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाकर 160-200 किलोमीटर प्रति घंटे की जाएगी।
- टिकट प्रणाली का आधुनिकीकरण। प्रति मिनट 7,200 टिकट जारी करने की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य।
- बेहतर उपयोग के लिए भूमि रिकार्ड का डिजिटीकरण होगा। बेहतर प्रबंधन और बेहतर आय के लिए पीपीपी मॉडल पर विचार।
- इन्नोवेशन इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना।
- महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए 4,000 महिला कांस्टेबल की तैनाती।
- पहले से पके हुए और खाने के लिए तैयार भोजन की व्यवस्था।
- क्षेत्रीय स्वाद के लिए प्रमुख स्टेशनों पर फूड कोर्ट की सुविधा। नई दिल्ली-अमृतसर और नई दिल्ली-जम्मू तवी मार्ग पर पायलट परियोजना।
- स्वच्छता पर खर्च में 40 फीसदी वृद्धि। स्टेशनों पर सफाई व्यवस्था की सीसीटीवी से निगरानी।
- स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं पर विशेष रेलगाड़ी।
- 2014-15 के लिए आय लक्ष्य 1,64,374 करोड़ रुपये, व्यय लक्ष्य 1,49,176 करोड़ रुपये।
- किराया वृद्धि से 8,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के लिए अतिरिक्त 9,000 करोड़ रुपये की जरूरत।
- रक्षा संस्थानों की आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़।
- एक अरब टन सालाना माल ढुलाई।
- 2013-14 में यात्री वृद्धि दर घटी।
- आधुनिकीकरण के लिए पांच साल में पांच लाख करोड़ रुपये की जरूरत।
- 2013-14 में 1,39,550 करोड़ रुपये आय, व्यय 1,30,321 करोड़ रुपये।
- प्रत्येक एक रुपये की आय के लिए 94 पैसे की व्यय। छह पैसे का मुनाफा।
- 12,500 रेलगाड़ियों से रोज 2.3 करोड़ यात्री सफर करते हैं, जो आस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है।
- विश्व में सबसे बड़ी माल ढुलाई सेवा बनने का लक्ष्य। ■

केंद्रीय रेल मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने 8 जुलाई 2014 को लोकसभा में रेल बजट प्रस्तुत किया, जिसके प्रमुख बिंदु हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं :-

बजट में नए प्रोत्साहन भारतीय रेलवे की कायापलट कर देंगे : सदानंद गौड़ा

केन्द्रीय रेल मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा कर्नाटक के दक्षिण कन्नड जिले से हैं और इस समय वे लोकसभा में बंगलौर उत्तरी निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने अपना राजनैतिक जीवन जनसंघ सदस्य के रूप में किया और भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने 1994 और 1999 में कर्नाटक विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे मंगलौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 2004 में 14वीं लोकसभा से निर्वाचित हुए और 2006 में उन्हें भाजपा का कर्नाटक प्रदेशाध्यक्ष चुना गया। उन्होंने पार्टी प्रदेशाध्यक्ष के रूप में उस समय राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त की जब बीजेपी ने मई 2008 में दक्षिण भारत से पहली बार विधानसभा चुनाव जीता। वे अगस्त 2011 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने से पहले उडुपी चिकमंगलुर निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए। हाल के आम चुनाव में 16वीं लोकसभा में निर्वाचित होने से पूर्व श्री सदानंद गौड़ा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री मंत्रिमण्डल में केन्द्रीय मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और उन्हें रेलमंत्री का कार्यभार सौंपा गया। श्री गौड़ा ने पहली बार रेल बजट पेश किया जिसमें उन्होंने भारतीय रेलवे को पटरी पर लाने के लिए अनेक सुधारों की घोषणा की।

'कमल संदेश' के लिए एक साक्षात्कार में सम्पादकीय बोर्ड के सदस्य श्री राम प्रसाद त्रिपाठी से बातचीत में श्री सदानंद गौड़ा ने भारतीय रेलवे के सामने आसन्न चुनौतियों और प्राथमिकताओं का उल्लेख किया। उन्होंने रेलवे की महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी सामने रखा और साफ-साफ स्वीकार किया कि भारतीय रेलवे के एक दशक के कुशासन के बाद उनकी सीमाएं बहुत कम बची रह गई हैं। उनके साक्षात्कार के कुछ अंश नीचे प्रस्तुत हैं:

- केन्द्रीय रेलमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने और अपना पहला रेल बजट पेश करने के लिए अनेक बधाइयां। आपने अपने रेल बजट में कुछ साहसिक निर्णय लिए हैं, और अनेक महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं। परन्तु, आज भारतीय रेलवे की वास्तविक स्थिति क्या है?

रेलवे बजट भारतीय रेलवे के भविष्य का एक विजन दस्तावेज है। मेरा विशेष ध्यान इस बात पर रहा है कि हम पुरानी गलत पद्धतियों से दूर हटें और भविष्य के लिए एक ठोस नींव रखें। मैंने अपने बजट में प्रतिष्ठित प्रकार के वायदे नहीं किए हैं। मेरी कोशिश रही है कि रेलवे को नई दिशा दी जाए और स्पष्ट है कि इसके परिणाम आने में कुछ समय लगेगा।

किन्तु पिछले कुछ वर्षों में पहले की सरकारों ने भारतीय रेलवे की प्रणालीगत उपेक्षा करना सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है जिसने रेलवे की छवि को बुरी तरह से क्षत-विक्षत कर दिया। पिछले कई वर्षों में इतने अधिक घाटे इकट्ठे हो गये जिससे विगत 10 वर्षों में यूपीए सरकार द्वारा घोषित वर्तमान में चल रही परियोजनाओं के लिए बजट इमदाद के लिए लगभग कुछ भी बचा नहीं रह गया। उन्होंने भारतीय रेलवे सम्बन्धी हर बात का राजनीतिकरण किया और इस सेक्टर में विकास के लिए जरा भी कुछ नहीं किया। मुझे भविष्य के लिए एक नया रोड़मैप बनाने के लिए विरासत में मिली इस कठिनाई से जूझना था।

- रेल यात्रियों के लिए सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसे विषय चिंता का विषय हैं। आपने इन चिंताओं के समाधान के लिए बजट में कौन से कदम उठाए हैं?

मेरे बजट का मूल विषय ही गाड़ियों में सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार करना है। गाड़ियों में सुविधाएं प्रदान

करने से बचा नहीं जा सकता। वास्तव में यात्रियों को बढ़े किराए मंजूर हैं बशर्ते कि उन्हें सही सेवाएं मिलें। जहां तक रेलवे में दिये जा रहे भोजन की किस्म की बात है, ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं जिससे यात्रियों को 'रेडी टू ईट फूड' दिया जाए तथा बेस किचन में भी हाइजीन सुनिश्चित की जाए। स्वच्छता चिंता का एक और विषय है। मोदी जी को शुरू से ही इस चुनौती से अवगत थे और इसलिए हमने सत्ता संभालते ही पहले दिन से पूरे देश में स्टेशनों पर स्वच्छता आंदोलन शुरू कर दिया। गाड़ियों और स्टेशनों दोनों पर शौचालयों की स्थिति इतनी खराब है कि लोग इन सुविधाओं से दूर रहना चाहते हैं। हमारी रेलों में स्वच्छता में सुधार करने के लिए मैंने इस सेक्टर के लिए बजट में विशाल 40 प्रतिशत की वृद्धि की है। हमने अपने बजट में सुरक्षा मुद्दों को भी प्राथमिकता दी है। अन्य क्षेत्रों में यातायात जमाव, बिना चौकीदार वाले क्रासिंग और गाड़ियों के अंदर सुरक्षा सम्बन्धी विषय हैं जिनका समाधान किया जाना है। गाड़ियों के अन्दर महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैंने कोचों में सीसीटीवी कैमरे, गाड़ियों में महिला आरपीएफ के लिए धनराशि आवंटित की है और इसके लिए हम गाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के लिए 4000 से अधिक महिला कांस्टेबल भर्ती करेंगे।

- आपने तेज गति से चलने वाली गाड़ियों के लिए डायमंड चतुर्भुजीय परियोजना की घोषणा की है जो भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ी छलांग होगी। इसका रोडमैप क्या है और कितने वर्षों में यह लागू हो पाएगा?

आज का उदीयमान भारत परिवर्तन चाहता है, जो वास्तव में समय के अनुकूल है। इसके लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है जो विश्व में सबसे उत्कृष्ट होना चाहिए। अत:, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने तेज गति और बुलेट गाड़ियों का वायदा चुनाव में किया था।

जैसा कि आप जानते हैं कि हाल में हमने दिल्ली से आगरा के बीच तेज गति चलने वाली गाड़ी का परीक्षण किया था और हमने देश के और आठ हिस्सों में भी इसकी बात कही है, जहां हम प्रारम्भिक दौर में तेज गति की गाड़ियां चलाएंगे। बुलेट गाड़ी एक और कंसेप्ट है। स्वर्णिम चतुर्भुजीय परियोजना, जिसकी शुरूआत पिछली एनडीए सरकार के दौरान श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, श्री मोदी ने भी डायमण्ड चतुर्भुजीय परियोजना का प्रस्ताव किया है जो महानगरों सहित देश के सभी भागों को जोड़ेगी। इसके लिए हमने बजट में प्रावधान किया है और अगले कुछ महीनों में हमें जेआईसीए से इसकी व्यावहारिक रिपोर्ट मिल जाएगी। हम उनकी व्यावहारिकता के आधार पर आगे बढ़ेंगे। अगले 4-5 वर्षों में मुझे उम्मीद है कि मुम्बई से अहमदाबाद के हिस्से में प्रारम्भिक दौर में काम शुरू हो जाएगा और उसके बाद हम इस नेटवर्क का विस्तार करेंगे। पूरे देश में इस महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी करने के लिए 10 वर्ष और लगेंगे।

- रेलवे के विकास के लिए संसाधन-संग्रह का भारी संकट है। आप कौन से तरीके अपनाएंगे जो आपसे पहले के मंत्रियों ने नहीं अपनाए?

दो बातें हैं। रेलवे की संचालन लागत लगभग 94 प्रतिशत है। अत: पहले तो हमें यह संचालन लागत कम करनी होगी और दूसरे हमें सुनिश्चित करना होगा कि रेलवे में कुछ चुनिंदा सेक्टरों में विकास के लिए कुछ निजी लोग भी सामने आएं। हम बुलेट गाड़ियों के लिए, फ्रंट कॉरीडोर और हाई स्पीड गाड़ियों के लिए एफडीआई को भी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। परन्तु, कोर आप्रेशन एरिया रिंग-फैंस्ट है और किसी को भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाएगा। अन्य बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल परियोजनाओं के लिए हम निश्चित ही एफडीआई और विजीबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीपी) रूट्स पर विचार करेंगे। निजी लोग 15000 करोड़ से अधिक का निवेश औद्योगिक तथा पोर्ट कनेक्टिविटी एवं वैगन मैन्युफैक्चरिंग परियोजना में निजी लोग प्रमुख भूमिका अदा कर सकते हैं जिससे अन्तत: रेलवे तथा लोगों को लाभ मिलेगा।

- स्वतंत्रता के 67 वर्षों बाद दक्षिण ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के हिस्सों में आज भी अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। इस बात को देखते हुए कि इन क्षेत्रों में परियोजनाएं अलाभकारी रहेंगी, क्या फिर भी आप इन परियोजनाओं को प्राथमिकता देंगे?

देखिए, विगत में क्या हुआ? मेरा मानना है कि अगले चार-पांच वर्षों में, हर अनकनेक्टिड क्षेत्र की प्रमुख शहरों को कनेक्टिविटी दी जाएगी। इसे पूरा करने के

लिए हमने कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में राष्ट्रीय परियोजना के रूप में कुछेक परियोजनाएं चलाई हैं, जिसके लिए विशेष धनराशि रखी जाएगी और अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान इसमें बाधक नहीं बनेगा। इस बात का ध्यान में रखते हुए हमने इस बजट में कोई नया प्रोजेक्ट अपने हाथ में नहीं लिया है क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता वर्तमान परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक बड़ी भारी रकम 5 लाख करोड़ रुपए की है और अधिशेष के रूप में केवल 30 करोड़ रुपए ही उपलब्ध हैं। अत: हमने पूरा न हुए कामों को प्राथमिकता दी है और हमारा अगला कदम अभी तक अनकनेक्टेड क्षेत्रों को कनेक्टेड में बदलने का रहेगा।

- ओडिशा, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में हर वर्ष साइक्लोन आने के कारण स्टेशनों का हाल बुरा रहता हैं जैसा कि आप जानते भी हैं कि पिछले वर्ष फालीन साइक्लोन से ओड़िशा में बरहमपुर जैसा प्रमुख स्टेशन पूरी तरह से क्षत-विक्षत हो गया था। क्या आप बार-बार आने वाली इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण कम से कम विनाश हो, कोई योजना है?

यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे शामिल करना जरूरी है। पहले तो हम ऐसे क्षेत्रों का पता लगा रहे हैं, जो बार-बार ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो जाते हैं। हम ऐसा ढांचा चाहते हैं, जहां बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं को रोका जा सके और यात्रियों तथा रेलवे सम्पदा की सुरक्षा की जा सके।

- इस समय रेलवे अधिकांश रूटों पर भारी यात्री ट्रैफिक महसूस कर रहा है जिससे यात्रियों की लम्बी प्रतीक्षा सूची बन जाती है और इन यात्रियों का एजेंट लोग लाभ उठाते रहते हैं। प्रमुख रूटों पर शून्य-प्रतीक्षा सूची सुनिश्चित करने के लिए आपका क्या प्रस्ताव है?

हमने टिकट बुकिंग में कहीं अधिक आईटी-आधारित पहल की हैं और उच्च टैक्नोलॉजी के कारण जल्द ही हम आईआरसीटीसी आन-लाइन बुकिंग प्रणाली के माध्यम से प्रति मिनट 300 प्रतिशत से अधिक टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं। हम बुकिंग प्रणाली के मैकेनिकल मोड़ पर चलना चाह रहे हैं जिससे हमें प्रतीक्षा सूची को कम करने की उम्मीद है। उच्च गति गाड़ियों की शुरूआत करने से भी वर्तमान स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी।

- पश्चिम के कई देशों में अपनी रेलवे प्रणाली में नान-कंवेशनल एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या आप भी भारतीय गाड़ियों को इसी एनर्जी का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं?

यह एक अच्छा सुझाव है। संचालन लागत में कटौती करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। बिजली का प्रयोग डीजल प्रयोग से अपेक्षाकृत सस्ता बैठता है। अत:, पहले तो हमारा प्रयास रहेगा कि सभी रूटों का विद्युतीकरण किया जाए। कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने सोलर पैनल से रूफटॉप में परिवर्तित करने की बात कही थी। हम इसी लाइन पर विचार कर रहे हैं और देश के सभी स्टेशनों में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने में कोई कोर कसर नहीं छोंड़ेंगे। सोलर एनर्जी के बारे में हमारा प्रारम्भिक लक्ष्य 500 मैगावाट का है। हम इसे प्राप्त कर लेंगे और हमने पवनचक्की स्थापना करने के लिए भी कुछेक स्थानों को चुना है।

- महोदय, आपने अपने बजट भाषण में रेलवे युनीवर्सिटी का उल्लेख किया था। इसकी प्रकृति और उद्देश्य क्या होगा और इसकी शुरूआत कब होगी?

एचआरडी मंत्रालय के साथ मिलकर हम इस समय इसका पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लोग रेलवे सेक्टर में भरती होने वाले हैं, उन्हें अच्छे से अच्छे प्रशिक्षण तथा टेक्नालॉजी का ज्ञान हो। हमें नवीन अविष्कारों को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है और अपनी जरूरतों के मुताबिक अपनी प्रणाली तैयार करना भी जरूरी है। हमने ऐसे कुछ क्षेत्रों का पता भी लगाया है, हमारे पास अपनी भूमि और इंफ्रास्ट्रक्चर है तथा यूनीवर्सिटी अगले कुछ वर्षो में शुरू हो जाएगी।

- भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई लाने का आपका प्रस्ताव है। ऐसे कौन से सेक्टर हैं और क्या एफडीआई से रेलवे के संसाधनों का निराकरण हो सकेगा?

मेरे विचार में एफडीआई से भारतीय रेलवे का मनोबल बढ़ेगा। उच्च गति गाड़ियों की सेवाएं, बुलेट ट्रेन, फ्रेट

कॉरीडोर और इंटरनेशनल स्टैण्डर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों को लाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर ऐसी सुविधाएं जुटाने के लिए एफडीआई आवश्यक है। परन्तु कोर आप्रेशनल एरिया सदैव रेलवे विभाग के पास रहेगा। मैं निश्चित ही यह सोचता हूं कि यदि हम बड़े पैमाने पर एफडीआई ला पाए तो इससे संसाधनों की समस्या का हल निकल सकेगा तथा भारतीय रेलवे को आधुनिक कटिंग-एज टेक्नालॉजी का लाभ मिलेगा।

- महोदय, क्या आप विभिन्न राज्यों में वर्तमान रेलवे परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव बना रहे हैं?

इस समय भी कुछ राज्य सहयोग कर रहे हैं। वे हमें नि:शुल्क भूमि दे रहे हैं और अपने-अपने राज्यों में रेलवे परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन के लिए परियोजनाओं की लागत का 50 प्रतिशत अंशदान कर रहे हैं। अब, भूमि अधिग्रहण और संसाधन-संग्रह प्रमुख समस्याएं हैं। अत:, निश्चित ही राज्य सरकारों ने सहयोग की आवश्यकता है। सभी राज्यों को भागीदार बनाने के लिए मैंने इस बारे में मुख्य मंत्रियों को उनके सहयोग के लिए पत्र लिखा है और उन सभी से बात की है कि वे परियोजनाओं के 50 प्रतिशत का अंशदान और नि:शुल्क भूमि देने में हमें अपनी सहायता दें। विशिष्ट रूप से, मैं चाहूंगा कि वे फ्रेट कारीडोर के कार्यान्वयन में सभी राज्य हमारा सहयोग करें। आखिरकार, लिंकेज से राज्यों के विकास में मदद मिलेगी और मुझे उम्मीद है कि वे इस विषय में हमारे साथ आएंगे।

- हाल ही में आपने बैंगलोर रेलवे स्टेशन का अचानक दौरा किया था। वहां आपको क्या अनुभव हुआ और क्या आप पूरे देश में इसे अपनाएंगे?

मैं वहां बिना किसी मीडिया के प्रात: 6 बजे गया था। मेरे निजी स्टाफ को छोड़कर मैंने डीआरएम तक को भी कोई सूचना नहीं दी। मैंने वहां शौचालय, रसोई घर, पेयजल, टिकट काउंटर सहित अनेक यात्री सुविधाओं को देखा और मुझे वहां अनेक खामियां देखने को मिली, जिन पर कार्रवाई करना आवश्यक है। मैंने द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में यात्रा की, लोगों के साथ बातचीत की और कंपार्टमेंट और शौचालय में साफ-सफाई ठीक नहीं देखी। मैंने अधिकारियों और सम्बंधित अथारिटीज को निर्देश दिए कि वे भविष्य में ऐसे मामलों को ध्यान में रख कर काम करें और उन्होंने इस बात का सकारात्मक रूप में ग्रहण किया। मेरी इस विजिट से न केवल मुझे अनुभव प्राप्त हुआ बल्कि इससे मेरा दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हुआ कि भारतीय रेलवे में होने वाली खामियां दूर होनी चाहिए। आगे आने वाले समय में, मैं देश के अन्य भागों में ऐसी विजिट करूंगा।

- भारतीय रेलवे में लोग कब तक बदलाव करने की उम्मीद कर सकते हैं?

निश्चित ही रेलवे को प्रत्यक्ष परिवर्तन के लिए समय और संसाधनों की आवश्यकता है। किन्तु, हमने इसी बीच कई तात्कालिक कदम उठाए हैं ताकि गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सके। हमने बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान शुरू किया है। मैंने डीआरएम को आदेश दिया है कि वे स्टेशनों पर हाईजीन तथा स्वच्छता पर निगरानी रखने के लिए प्रतिदिन स्टेशनों, किचन और केटरिंग क्षेत्रों का दौरा करें तथा लोगों को जागरूक बनाएं और उनसे सहयोग की बात करें। भारतीय रेलवे को एक नए स्तर पर लाने के लिए लोगों की जागरूकता और समर्थन अत्यावश्यक है। ■

इतिहास के दागदार पन्ने

✍ बलबीर पुंज

15 अगस्त को भारत को स्वाधीन हुए 67 वर्ष हो जाएंगे। स्वतंत्रता की इस वर्षगांठ से पूर्व एक राष्ट्र के रूप में हमें इस बात पर आत्मचिंतन करना चाहिए कि इतने लंबे काल में हम देश से गरीबी दूर क्यों नहीं कर पाए, देश में एकता और विश्वास की भावना सुदृढ़ क्यों नहीं कर पाए और विश्व में अपने लिए वह स्थान क्यों नहीं सुनिश्चित कर पाए जिसके हम अधिकारी हैं? क्या यह कटु सत्य नहीं कि 14 अगस्त, 1947 तक यदि हम पर विदेशियों का शासन था तो 15 अगस्त, 1947 के बाद उन लोगों ने हम पर राज किया, जिनका नियंत्रण विदेशियों के हाथ में था अर्थात हमारे द्वारा चुने हुए शासक विदेशी ताकतों की कठपुतली थे। उनकी नीतियां देशहित में न होकर उन विदेशियों के हितों के लिए होती थीं जो उनका वित्तापोषण करते थे। क्या इसी तरह मीडिया का एक प्रभावी वर्ग भी विदेशी पैसे की खुराक पर जिंदा नहीं रहा और उसने देशहित में काम न कर अपने विदेशी आकाओं के हितों की चिंता की? ये सारे प्रश्न विगत लंदन के कैंब्रिज विश्वविद्यालय में सोवियत संघ की गुप्तचर संस्था केजीबी के हजारों गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक किए जाने के बाद प्रासंगिक हो गए हैं।

खुफिया इतिहासकार क्रिस्टोफर एंड्रयू और वासिली मित्रोखिन के संयुक्त प्रयास से दुनिया भर के देशों में केजीबी द्वारा चलाए गए खुफिया अभियानों का खुलासा 2005 में प्रकाशित पुस्तक-मित्रोखिन आर्काइव में किया गया था। बाद में इसका दूसरा खंड भी प्रकाशित हुआ। वासिली मित्रोखिन केजीबी के अभिलेखागार में वरिष्ठ संग्राहक थे। 1972 से 1984 के बीच प्रायरू प्रतिदिन केजीबी के अत्यंत गोपनीय दस्तावेजों को वह अपने साथ चोरी-छिपे बाहर लाते रहे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी एसआइएस से डील कर दस्तावेजों के बदले में लंदन में शरण ले ली। शीत युद्ध के दौरान केजीबी की सक्रियता भारत में सर्वाधिक थी। स्टालिन भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पिट्ठू समझते थे। स्टालिन ने गांधीजी को स्वतंत्रता सेनानी के भेस में लोगों से विश्वासघात करने वाला बताया था। वह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के भी मुखर आलोचक थे। स्टालिन के विरोधी रवैये के बावजूद पंडित नेहरू का अटूट विश्वास था कि सोवियत क्रांति ने मानवता की बड़ी सेवा की है। किंतु कटु सत्य यह है कि 1950 के प्रारंभिक वर्षो तक इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के लिए मास्को से जो भी आदेश-निर्देश आता था उसमें नेहरू सरकार को यथाशीघ्र उखाड़ फेंकने की बात होती थी।

एक ओर पंडित नेहरू आश्वस्त थे, वहीं मित्रोखिन के अनुसार मास्को स्थित भारतीय दूतावास में केजीबी के गुप्तचरों की पैठ बढ़ती ही जा रही थी। सुरा और सुंदरियों के मायाजाल में दूतावासकर्मी केजीबी के मोहरे बन रहे थे। मास्को ने नेहरू के विश्वासपात्र सलाहकार और विचारधारा से कम्युनिस्ट कृष्ण मेनन को प्रोत्साहित करना शुरू किया, जो साल 1957 में देश के रक्षा मंत्री बने। कृष्ण मेनन के दौर में ही देश के रक्षा उपकरणों की खरीद नीति पश्चिम से हटकर सोवियत संघ पर केंद्रित हुई। अक्टूबर,

1970 के दशक के प्रारंभ में ही भारत के सत्ता अधिष्ठान में केजीबी का पूरा दबदबा कायम हो चुका था। ओलेग कालूजिन जो बाद में काउंटर इंटेलिजेंस का मुखिया बना, तत्कालीन भारत को याद करते हुए कहता है कि तब सरकार, खुफिया विभाग, रक्षा, विदेश मंत्रालय और पुलिस में उसके सैकड़ों विश्वस्त संपर्क सूत्र काम कर रहे थे। एक मंत्री ने 50,000 डॉलर के बदले में अहम जानकारी देने का वादा किया था। कालूजिन के अनुसार ऐसा लगता था कि पूरा देश बिकने को तैयार है। उसके मुताबिक स्वयं इंदिरा गांधी के यहां नियमित रूप से नोटों से भरे सूटकेस भेजे जाते थे। केजीबी पर विश्वास का यह नतीजा था कि इंदिरा भारत में होने वाली किसी भी गड़बड़ी के लिए सीआइए को कसूरवार बताती थीं। इस मानसिकता के विरोध में पीलू मोदी 'मैं सीआइए एजेंट हूं' की तख्ती लगाकर संसद पहुंचे थे।

1962 में चीन के हाथों भारत को शर्मनाक पराजय का मुंह देखना पड़ा। नेहरू और कम्युनिस्ट मेनन चीन की विस्तारवादी कुटिलता के मूकदर्शक बने रहे। मेनन ने खुफिया सूचनाओं के बावजूद सेना को साधनविहीन रखा। भारी दबाव में नेहरू को मेनन को हटाना पड़ा। सोवियत संघ ने मेनन को दोबारा बहाल करने के लिए उनके पक्ष में प्रचार अभियान छेड़ा। अखबार वालों को धन देकर मेनन की तारीफ में लेख प्रकाशित कराए गए। मित्रोखिन के अनुसार भारत के दस बड़े प्रकाशन समूह केजीबी के पेरोल पर थे, जो केजीबी के हितों के अनुकूल लेख प्रकाशित करते थे। जनवरी, 1966 में लालबहादुर शास्त्री की ताशकंद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। कांग्रेस ने नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के लिए आगे किया, जिसे केजीबी ने 'वानो' का छद्म नाम दिया था। केजीबी को विश्वास था कि श्वानोश को अपनी शतरें पर काम करने के लिए तैयार कर लेगा। नवंबर, 1969 में कांग्रेस दोफाड़ हुई और कांग्रेस अस्तित्व में आई। मित्रोखिन लिखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अब 'दरबार संस्कृति' पैदा होने लगी। पार्टी का एक धड़ा मानता था कि इंदिरा गांधी देश को सोवियत संघ के हाथों बेचने पर आमादा हैं और मास्को और सोवियत दूतावास के बीच संपर्क सूत्र के रूप में अपने मुख्य सचिव परमेश्वर नारायण हकसर का उपयोग कर रही हैं।

1970 के दशक के प्रारंभ में ही भारत के सत्ता अधिष्ठान में केजीबी का पूरा दबदबा कायम हो चुका था। ओलेग कालूजिन जो बाद में काउंटर इंटेलिजेंस का मुखिया बना, तत्कालीन भारत को याद करते हुए कहता है कि तब सरकार, खुफिया विभाग, रक्षा, विदेश मंत्रालय और पुलिस में उसके सैकड़ों विश्वस्त संपर्क सूत्र काम कर रहे थे। एक मंत्री ने 50,000 डॉलर के बदले में अहम जानकारी देने का वादा किया था। कालूजिन के अनुसार ऐसा लगता था कि पूरा देश बिकने को तैयार है। उसके मुताबिक स्वयं इंदिरा गांधी के यहां नियमित रूप से नोटों से भरे सूटकेस भेजे जाते थे। केजीबी पर विश्वास का यह नतीजा था कि इंदिरा भारत में होने वाली किसी भी गड़बड़ी के लिए सीआइए को कसूरवार बताती थीं। इस मानसिकता के विरोध में पीलू मोदी 'मैं सीआइए एजेंट हूं' की तख्ती लगाकर संसद पहुंचे थे।

12 जून, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्वाचन को निरस्त किए जाने की घटना को भी इंदिरा गांधी ने विदेशी साजिश बताया। इसी आरोप में विपक्ष के प्रमुख नेताओं सहित 1,10,000 बेकसूर लोग जेलों में बंद कर दिए गए। इंदिरा गांधी के इस तुगलकी निर्णय को उचित ठहराने के लिए केजीबी ने 1.06 करोड़ रूबल दुष्प्रचार में खर्च किए। सीपीआइ को भारी धनराशि देकर इंदिरा गांधी को समर्थन दिलाया गया। इसी तरह ऑपरेशन ब्लूस्टार को तर्कसंगत साबित करने के लिए केजीबी ने भारी-भरकम राशि खर्च की। वामपंथी विचारधारा और मास्को निर्देशित समाजवादी अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक चलाए रखने के कारण एक ओर देश जहां 1991 आते-आते कंगाली की कगार पर आ खड़ा हुआ वहीं अप्रासंगिक विचारधारा को गले लगाए रखने के कारण सोवियत संघ स्वयं कई टुकड़ों में बंट गया। सोवियत संघ के विखंडित होते ही भारत में उस कुत्सित विचारधारा को पुष्ट करने वाली धारा सूख गई और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बेड़ियां थीं वे टूटनी शुरू हुई। उसका परिणाम है कि आज हम अविकसित देश से विकासशील देशों की पंक्ति में अग्र श्रेणी में खड़े हैं। प्रश्न उठता है कि जिन नेताओं, मीडियाकर्मियों और राजनीतिक दलों ने भारत की जनता का शोषण किया, क्या इतिहास उन्हें माफ करेगा? क्या यह छद्म युद्ध नक्सलवादियों और एनजीओ के माध्यम से भारत की भौगोलिक और आर्थिक संप्रभुता के खिलाफ जारी नहीं है? केवल आका और प्यादे ही बदले हैं, खेल आज भी दूसरे रूप में जारी है।■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं)

(साभार : दै. जागरण)

वामपंथी विचारधारा और मास्को निर्देशित समाजवादी अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक चलाए रखने के कारण एक ओर देश जहां 1991 आते-आते कंगाली की कगार पर आ खड़ा हुआ वहीं अप्रासंगिक विचारधारा को गले लगाए रखने के कारण सोवियत संघ स्वयं कई टुकड़ों में बंट गया। सोवियत संघ के विखंडित होते ही भारत में उस कुत्सित विचारधारा को पुष्ट करने वाली धारा सूख गई और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बेड़ियां थीं वे टूटनी शुरू हुईं। उसका परिणाम है कि आज हम अविकसित देश से विकासशील देशों की पंक्ति में अग्र श्रेणी में खड़े हैं।

मजबूत जनादेश की झलक

✍ ए. सूर्यप्रकाश

नरेंद्र मोदी को एक ऐसा प्रधानमंत्री माना जाता है जो कड़े निर्णय लेते हैं। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर भी देखा जाता है जो जरूरत पड़ने पर अलोकप्रिय निर्णयों से भी पीछे नहीं हटते। अपनी सरकार के पहले बजट में मोदी ने अपनी इस छवि को पुष्ट किया है और साफ कर दिया कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये वह कड़वी दवा के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेंगे। केंद्रीय बजट के संदर्भ में जनता को कुछ कड़े उपायों के अपनाये जाने की प्रत्याशा थी, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। इस क्रम में कड़वी दवा रेल भाड़े में 14 फीसद की बढ़ोतरी और बजट से पूर्व पेट्रोल, गैस की कीमतों में वृद्धि रही। हालांकि आम बजट में सरकार ने करदाताओं को कुछ राहत भी प्रदान की है।

केंद्रीय बजट में सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र को सुधारने के लिये कदम उठाने, बुनियादी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, विदेशी निवेशकों को प्रेरित करने के साथ-साथ रोजगार सृजन के माध्यम से युवाओं को सशक्त करने के उपायों की घोषणा की है। रेलवे बजट में भी व्यावहारिक कदमों पर जोर दिया गया और रेलवे की वित्तीय हालत में सुधार पर बल देने के साथ ही पहले से चल रही परियोजनाओं को पूरा करने, रेलवे की सुरक्षा में सुधार और सफाई व गति बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। देश की अर्थव्यवस्था का संचालन जिस तरीके से मनमोहन सिंह ने किया, उसके दृष्टिगत यह अवश्य कहा जा सकता है कि मोदी

सौभाग्य से रेल मंत्री सदानंद गौड़ा और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अनावश्यक लोकप्रियता से बचते हुए और व्यावहारिक रास्ते का चुनाव करते हुए रेल बजट व आम बजट प्रस्तुत किया। यही कारण है कि प्रधानमंत्री और उनकी टीम प्रशंसा की पात्र हैं, जिन्होंने विरासत में प्राप्त खराब आर्थिक हालात की चुनौती को स्वीकार करते हुए भारत की वित्तीय दशा को सुधारने का निर्णय लिया। सरकार ने 2014 के बजट को समग्र आर्थिक विकास के मद्देनजर विजन के रूप में प्रस्तुत किया। चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री ने जनता से सभी घरों को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था। मोदी सरकार ने इस दिशा में सही कदम उठाते हुए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिये धन आवंटित किया है।

सरकार ने अपने पहले रेल और आम बजट में जिम्मेदारी का परिचय देते हुए निरंतरता को कायम रखा और जहां जरूरी था वहां बदलाव भी किये। उदाहरण के तौर पर रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने संसद में बताया कि पिछले 10 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 99 नई लाइनें बिछाने की योजनाओं की घोषणा की गयी, लेकिन महज एक ही योजना को पूरा किया गया।

इसी तरह चार परियोजनायें ऐसी हैं जिन्हें 30 वर्ष पहले शुरू किया गया, लेकिन आज भी वे पूरी नहीं हो सकी हैं। इस क्रम में पूर्व की सरकारों ने लोकप्रियता का ध्यान रखा और परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर बल देने के बजाय नई योजनाओं को मंजूरी देती रहीं। इसका नतीजा यह रहा कि पिछले तीन दशकों में 1,57,883 करोड़ रुपये लागत वाली 676 परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी, जिनमें से आधी से भी कम पूरी हुई। आश्चर्यजनक यह है कि इन अधूरी परियोजनाओं की लागत अब बढ़कर 1,82,000 करोड़ रुपये पहुंच गयी है। मोदी सरकार ने इन अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने और गड़बड़ियों को दूर करने का निर्णय लिया है। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि अपने कार्यकाल के 10 वर्षों में मनमोहन सिंह घोषित 99 परियोजनाओं में से महज एक को ही पूरा कर सके। यह अर्थव्यवस्था को लेकर उनकी समझ तथा नेतृत्व क्षमता पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है।

सौभाग्य से रेल मंत्री सदानंद गौड़ा और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अनावश्यक लोकप्रियता से बचते हुए और व्यावहारिक रास्ते का चुनाव करते हुए रेल बजट व आम बजट प्रस्तुत किया। यही कारण है कि प्रधानमंत्री और उनकी टीम प्रशंसा की पात्र हैं, जिन्होंने विरासत में प्राप्त खराब आर्थिक हालात की चुनौती को स्वीकार करते हुए भारत की वित्तीय दशा को सुधारने

का निर्णय लिया। सरकार ने 2014 के बजट को समग्र आर्थिक विकास के मद्देनजर विजन के रूप में प्रस्तुत किया। चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री ने जनता से सभी घरों को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था। मोदी सरकार ने इस दिशा में सही कदम उठाते हुए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिये धन आवंटित किया है। प्रधानमंत्री युवाओं के दक्षता-विकास पर भी जोर देते रहे हैं, ताकि नियोक्ता की जरूरतों के अनुरूप वे योग्यता हासिल कर सकें। इसके लिये बजट में नेशनल मल्टी स्किल मिशन की बात कही गयी है।

स्वच्छ भारत अभियान मोदी की एक अन्य पसंदीदा योजना है, इसके लिये बजट में पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इसके तहत 2019 तक सभी घरों में शौचालय सुनिश्चित कराने का लक्ष्य है। अपने चुनाव अभियान के क्रम में जब मोदी वाराणसी पहुंचे तो उन्होंने जनता से कहा था कि वह इस पवित्र नगरी में मां गंगा के बुलावे पर आये हैं। पवित्र गंगा के प्रति मोदी ने अपना आदर-भाव दिखाया और इस शहर को नमामि गंगा योजना के तहत बजट में जेटली ने 2,000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की। गंगा जलमार्ग के लिये भी 4,200 करोड़ रुपये आवंटित किये।

इसके अतिरिक्त वाराणसी, हरिद्वार और गंगा के किनारे स्थित अन्य तीर्थ केंद्रों के घाटों की मरम्मत तथा जीर्णोद्धार के लिये 100 करोड़ आवंटित किये गये। चुनाव अभियान में मोदी ने हिमालय क्षेत्र और पूर्वोत्तार राज्यों के विकास पर जोर दिया था। इसके मद्देनजर पूर्वोत्तर में रेल परियोजनाओं के लिये अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया तथा मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय के लिये धन स्वीकृत किया गया।

राजनीतिक महत्व की दृष्टि से देखें तो पिछले 30 वर्षों में यह पहला केंद्रीय बजट है जिसे बहुमत प्राप्त किसी एक दल ने पेश किया है। इससे पहले 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में भारी बहुमत हासिल करने वाली कांग्रेस सरकार के समय ऐसा हुआ था, इसलिये मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को बिना किसी बाधा के स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार है। हालांकि इस तरह की स्वतंत्रता की स्थिति में सरकार किसी निर्णय को लेने अथवा न लेने के लिये कोई बहाना नहीं बना सकती। केंद्रीय बजट की दिशा देखते हुए हम कह सकते हैं कि जनादेश के अनुरूप मोदी सरकार ने अपना सर्वोत्ताम काम किया है और कुछ ऐसे निर्णय लिये हैं जिन्हें कोई गठबंधन सरकार शायद ही ले पाती।

उदाहरण के तौर पर सब्सिडी उपायों की समीक्षा के लिये एक्सपेंडीचर मैनेजमेंट कमीशन अथवा व्यय प्रबंधन आयोग का गठन। इस मद में प्रति वर्ष उपभोक्ताओं को 2।6 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है। यह निर्णय कांग्रेस समेत अन्य सभी राजनीतिक दल वोट बैंक की खातिर शायद ही ले पाते।

इसी प्रकार गंगा की सफाई और घाटों की मरम्मत आदि के लिये 2,000 करोड़ देने का निर्णय तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीति के चलते शायद ही हो पाता। वामपंथी पार्टियों पर निर्भर कोई सरकार बीमा और रक्षा क्षेत्र में एफडीआइ बढ़ाने का निर्णय नहीं ले सकती थी।

नरेंद्र मोदी तमाम राजनीतिक बाध्यताओं से मुक्त हैं और इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की प्राथमिकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। इससे एक बार फिर देश उच्च विकास दर की राह पर अग्रसर हो सकेगा। ■

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

(साभार : दै. जागरण)

केंद्रीय बजट की दिशा देखते हुए हम कह सकते हैं कि जनादेश के अनुरूप मोदी सरकार ने अपना सर्वोत्ताम काम किया है और कुछ ऐसे निर्णय लिये हैं जिन्हें कोई गठबंधन सरकार शायद ही ले पाती। उदाहरण के तौर पर सब्सिडी उपायों की समीक्षा के लिये एक्सपेंडीचर मैनेजमेंट कमीशन अथवा व्यय प्रबंधन आयोग का गठन। इस मद में प्रति वर्ष उपभोक्ताओं को 2।6 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है। यह निर्णय कांग्रेस समेत अन्य सभी राजनीतिक दल वोट बैंक की खातिर शायद ही ले पाते।

गंगा की सफाई और घाटों की मरम्मत आदि के लिये 2,000 करोड़ देने का निर्णय तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीति के चलते शायद ही हो पाता। वामपंथी पार्टियों पर निर्भर कोई सरकार बीमा और रक्षा क्षेत्र में एफडीआइ बढ़ाने का निर्णय नहीं ले सकती थी। नरेंद्र मोदी तमाम राजनीतिक बाध्यताओं से मुक्त हैं और इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की प्राथमिकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। इससे एक बार फिर देश उच्च विकास दर की राह पर अग्रसर हो सकेगा।

मुद्दा : नेशनल हेराल्ड का स्वामित्व प्रकरण

एक और विवादित बिजनेस मॉडल

राजीव सचान

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र की नियुक्ति वाले संशोधन विधेयक पर कांग्रेस का अलग-थलग पड़ना उसकी राजनीतिक मुसीबत को बयान करता है। आने वाले दिनों में कांग्रेस की कानूनी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि दिल्ली की एक अदालत ने उन आरोपों को प्रथम दृष्ट्या सही मान लिया है जिनमें कहा गया है कि सोनिया और राहुल गांधी ने यंग इंडिया कंपनी के जरिये नेशनल हेराल्ड का स्वामित्व रखने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स को अनुचित-अवैधानिक तरीके से हासिल किया है। एसोसिएटेड जर्नल्स पर कब्जा कर सोनिया-राहुल और उनके कुछ अन्य करीबी नेशनल हेराल्ड की करीब दो हजार करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति के स्वामी बन गए हैं। इनमें से कुछ संपत्ति को किराए पर देकर वे व्यावसायिक लाभ भी ले रहे हैं। इसके बावजूद नेशनल हेराल्ड के फिर से प्रकाशित होने के आसार दूर-दूर तक नहीं नजर आते। इस मामले के सतह पर आते ही आयकर विभाग सक्रिय हो गया और उसने सोनिया-राहुल को नोटिस जारी कर दिए। इस पर खुद सोनिया गांधी की ओर से कहा गया कि यह बदले की कार्रवाई है और इससे कांग्रेस को फिर से मजबूत होने में मदद मिलेगी। उनके इस कथन के बाद अन्य कांग्रेसी भी यह कहने में जुट गए कि मोदी सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। कोई भी यह नहीं बता रहा कि कांग्रेस ने यंग इंडिया के जरिये एसोसिएटेड जर्नल्स को कर्ज देने का काम क्यों किया और वह भी तब जब नियम-कानून राजनीतिक दलों को ऐसा करने से रोकते हैं?

सोनिया-राहुल को सम्मन जारी करने वाली अदालत ने खुद यह कहा है कि साक्ष्यों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि यंग इंडिया का गठन एक पाखंड के रूप में किया गया ताकि सार्वजनिक धन को निजी संपत्ति में तब्दील किया जा सके यानी एसोसिएटेड जर्नल्स की दो हजार करोड़ की संपत्ति पर नियंत्रण हासिल किया जा सके इसलिए मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश बेकार है। अदालत ने यह भी कहा है कि पार्टी कोष का धन एसोसिएटेड जर्नल्स को ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में दिए जाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व कानून की कोई भी धारा या पार्टी का संविधान इसकी अनुमति नहीं देता।

इस सवाल के जवाब में कांग्रेसी प्रवक्ता यही कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड के प्रति कांग्रेस का भावनात्मक लगाव है और इसी नाते उसने उसका प्रकाशन करने वाली कंपनी की मदद की, लेकिन एक तो भावनात्मक लगाव नियम-कानूनों के उल्लंघन की इजाजत नहीं देते और दूसरे यदि कांग्रेस का इरादा नेशनल हेराल्ड को फिर से प्रकाशित करने का था तो फिर यह अखबार निकला क्यों नहीं? शायद उसका ऐसा कोई इरादा था ही नहीं, क्योंकि दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस का एक हिस्सा तो किराये पर दे दिया गया है। कांग्रेस की ओर से सफाई दी गई है कि यह किराया एसोसिएटेड जर्नल्स के पास जा रहा है, लेकिन अब यह कंपनी तो यंग इंडिया के अधीन है, जिसमें अधिकांश भागीदारी सोनिया और राहुल गांधी के पास है। जाहिर है कि इस पर सवाल तो उठेंगे ही। इन सवालों की अनदेखी सिर्फ इसलिए नहीं की जा सकती उन्हें उठाने का काम सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं। वैसे भी स्वामी के सवालों से दिल्ली की अदालत सहमत नजर आ रही है। इस अदालत के सम्मन पर सोनिया-राहुल के अलावा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, महासचिव आस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को भी उसके समक्ष हाजिरी बजानी है। चूंकि वे कानूनी लड़ाई की चपेट में आ गए हैं इसलिए उसे राजनीतिक लड़ाई की तरह नहीं लड़ सकते।

सोनिया-राहुल यह प्रतीति कराने की व्यर्थ ही कोशिश कर रहे हैं कि संप्रग सरकार की पराजय के साथ ही उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई शुरू हो गई है। सच्चाई यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले की तह तक जाने की कोशिश न जाने कब से कर रहे थे। जब उन्होंने तमाम प्रमाण जुटा लिए तभी अदालत ने सोनिया-राहुल को सम्मन

देना तय किया। चूंकि सोनिया-राहुल को सम्मन जारी करने वाली अदालत ने खुद यह कहा है कि साक्ष्यों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि यंग इंडिया का गठन एक पाखंड के रूप में किया गया ताकि सार्वजनिक धन को निजी संपत्ति में तब्दील किया जा सके यानी एसोसिएटेड जर्नल्स की दो हजार करोड़ की संपत्ति पर नियंत्रण हासिल किया जा सके इसलिए मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश बेकार है। अदालत ने यह भी कहा है कि पार्टी कोष का धन एसोसिएटेड जर्नल्स को ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में दिए जाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व कानून की कोई भी धारा या पार्टी का संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। आखिर अदालत की इन टिप्पणियों के बाद इस मामले में मोदी सरकार का दखल कहां नजर आ रहा है? क्या कोई मामला किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से उठाने पर राजनीतिक हो जाएगा जो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो? अगर इस तर्क को माना जाएगा तो फिर राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति तो किसी मामले को अदालत तक ले ही नहीं जा पाएंगे।

कम से कम कांग्रेस को तो यह अच्छे से स्मरण होगा कि किस तरह एक कांग्रेसी नेता की ओर से जया बच्चन को लेकर लाभ के पद का मामला उठाया गया था। बाद में खुद सोनिया गांधी भी इसकी चपेट में आ गई थीं। तब उन्हें लोकसभा चुनाव फिर से लड़ना पड़ा था, जिसे उन्होंने आसानी से जीत लिया था। यह कहना कठिन है कि वह नेशनल हेराल्ड मामले से भी आसानी से उबर जाएंगी।

पता नहीं सोनिया-राहुल इस मामले में अपना बचाव कैसे करेंगे और अदालत अंततः किस नतीजे पर पहुंचेगी, लेकिन यह समझना कठिन है कि एक से एक काबिल वकीलों से लैस कांग्रेस में से किसी ने सोनिया-राहुल को यह सलाह क्यों नहीं दी कि वह नेशनल हेराल्ड पर इस तरह से कब्जा नहीं कर सकते? किसी को यह भी बताना चाहिए था कि नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों से उस तरह व्यावसायिक लाभ नहीं उठाया जा सकता जैसे कि उठाया जा रहा है। कांग्रेसी नेताओं ने यंग इंडिया नामक कंपनी बनाकर जिस तरह एसोसिएटेड जर्नल्स को 90 करोड़ रुपये का बिना ब्याज के कर्ज दिया और फिर नेशनल हेराल्ड की सारी संपत्तियों के मालिक बन गए उससे राबर्ट वाड्रा का स्मरण हो आता है। उनकी जमीन की खरीद-फरोख्त करने वाली कंपनियां भी वित्तीय अनियमितताओं की कहानी कहती हैं। वाड्रा ने यह दावा किया था कि उनकी एक कंपनी को एक बैंक से करोड़ों रुपये का ओवरड्राफ्ट मिला, लेकिन उस बैंक ने ऐसा कोई ओवरड्राफ्ट देने से इन्कार किया। बावजूद इसके वाड्रा ने कोई सफाई पेश नहीं की। इसे संयोग कहें या दुर्योग कि वाड्रा और सोनिया-राहुल के बिजनेस मॉडल में अद्भुत साम्य दिख रहा है। ■

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं।)

नवगठित भाजपा संसदीय दल के पदाधिकारीगण

पद		नाम
	पार्टी के नेता	श्री नरेन्द्र मोदी
पार्टी के उपनेता		
	लोकसभा	श्री राजनाथ सिंह
	राज्यसभा	श्री अरुण जेटली
सरकारी मुख्य सचेतक		श्री एम. वेंकैया नायडू
सरकारी उप मुख्य सचेतक		
	लोकसभा	श्री संतोष गंगवार
	राज्यसभा	श्री प्रकाश जावडेकर
पार्टी के मुख्य सचेतक		
	लोकसभा	श्री अर्जुन राम मेघवाल (राजस्थान)
	राज्यसभा	श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब)
सचिव		
	लोकसभा	श्री गणेश सिंह (मध्यप्रदेश)
	राज्यसभा	श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान)
कोषाध्यक्ष		श्री पी.सी. मोहन (कर्नाटक)

भाजपा अनु.जनजाति मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी, रांची

भाजपा के विकास में आदिवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका : जुआल ओराम

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 19 जुलाई को संपन्न गई। बैठक में कांग्रेस के विकल्प के रूप में पार्टी के विकास इस समुदाय की भूमिका की प्रशंसा की गई तथा इस पर भी गौर किया गया कि झारखण्ड आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

झारखण्ड लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद पूर्ण विश्वास से भरपूर होकर पार्टी नेताओं ने राज्य के विधान सभा चुनावों में ऐसे ही प्रदर्शन को दोबारा दोहराने का अपना संकल्प व्यक्त किया।

केन्द्रीय जनजाति कार्य मंत्री श्री जुआल ओराम ने भाजपा के प्रति आदिवासियों की प्रतिबद्धता को दोहराया और भारतीय राजनीति में इस समुदाय के सदस्यों के महत्त्व की याद दिलाते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। केन्द्रीय मंत्री ने झारखण्ड आने वाले चुनावों में समुदाय के महत्व का दिग्दर्शन कराते हुए एसटी कार्यकर्ताओं की गहन सराहना की और कहा कि हमारा संकल्प रहेगा कि वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार को हटाया जाए। उन्होंने कहा भाजपा के विकास के लिए आदिवासियों का बहुत महत्व है।

श्री ओराम ने दो दिन की कांफ्रेंस का उद्घाटन किया। अनु. जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने श्री ओराम के विचारों से सहमत होते हुए यह भी कहा कि उन्होंने भाजपा के एसटी मोर्चा की कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए सही समय और सही स्थान चुना है। कुलस्ते का कहना था कि पार्टी इस समुदाय के लिए आरक्षित सभी सीटों पर विजयी रहेगी। श्री ओराम का कहना था कि आने वाले विधानसभा चुनावों में मोर्चा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस कांफ्रेंस का आयोजन आने वाले चुनावों को दृष्टि में रख कर किया गया है।

झारखण्ड के पूर्व मुख्य मंत्री श्री अर्जुन मुण्डा ने कहा कि विधान सभा चुनावों में भाजपा अधिक से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। जब केन्द्र में पूर्ण बहुमत लेकर भाजपा ने सरकार बनाई तो सचमुच यह एक नया इतिहास रचा गया और अब भाजपा सरकार झारखण्ड राज्य में भी बनेगी।

श्री मुण्डा ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार जनजाति समुदाय के खिलाफ है। राज्य में किसी प्रकार का विकास नहीं हो रहा है। केन्द्रीय मंत्री और लोहारदगा सांसद श्री सुदर्शन भगत का कहना था कि मोदी सरकार राज्य को सहायता प्रदान करेगी। दो दिन की कांफ्रेंस में केन्द्रीय मंत्री श्री मनसुखभाई वासवा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री रविन्द्र कुमार राय, भाजपा सांसद श्री लक्ष्मण गिलुआ, रांची की महापौर सुश्री आशा लाकरा और भाजपा एसटी विंग के 12 राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। ■

भाजपा बिहार प्रदेश कार्यकारिणी बैठक

भाजपा का लक्ष्य – 175 प्लस

भारतीय जनता पार्टी, बिहार प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 19 एवं 20 जुलाई 2014 को पटना के कैलाशपति मिश्र सभागार में मिशन 175 के संकल्प के साथ संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से तीन मुद्दों – लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी सफलता, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां और बिहार की बदहाल स्थिति पर चर्चा की गई।

बैठक का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में श्री रामलाल ने कार्यकर्ताओं से मंडल स्तर पर सक्रियता बढ़ाने, बूथ स्तर पर सामाजिक समीकरण मजबूत करने और एक-एक घर तक पहुंचने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि सूबे के 722 मंडलों की कार्यकर्ता बैठकों में प्रदेश पदाधिकारी, सांसद और विधायक जायेंगे। सांसद-विधायकों से उन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित करने की अपील की।

केंद्रीय कानून व संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा था कि भाजपा की हवा पंखा और ब्लोअर की हवा है। ऐसा कहनेवालों को अंदाजा लग गया है कि वह पंखा या ब्लोअर की नहीं, बल्कि जनता की हवा थी। उन्होंने कहा कि भाजपा-जदयू के बीच पहले दिल का रिश्ता था।

यह रिश्ता बिहार को ठीक करने के लिए बना था। आज जदयू-राजद के बीच जो रिश्ता बन रहा है, वह बिहार की बरबादी के लिए घबराहट का रिश्ता बन रहा है। सूबे की जनता खौफ की राजनीति को खत्म करेगी।

बिहार प्रदेश प्रभारी एवं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कार्यकर्ता हनुमान की तरह होते हैं। जरूरत उन्हें बल की याद दिलाने की

होती है। श्री प्रधान ने कटाक्ष करते हुए कहा कि एक तरह दिल्ली में कल्याणकारी सरकार चल रही है वहीं बिहार में सुशासन बाबू सरकार चला रहे हैं। उन्होंने बयान दिया है कि भाजपा ब्रांड बिहार खराब कर रही है। जनता सब देख रही है कि ब्रांड बिहार कौन खराब कर रहा है। जनता इसका जवाब देगी।

बैठक के दूसरे दिन विधान परिषद् में विपक्ष के नेता श्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यह जंगलराज-2 का संकेत है।

अब जंगलराज-2 में लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार भी हैं। इसे जनता समाप्त करेगी। श्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा।

बैठक में अध्यक्षीय भाषण देते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगल पांडेय ने कहा कि बिहार में भाजपा 175प्लस की आंकड़ा लेकर चल रही है। हमें उम्मीद है कि राज्य में 175 से ज्यादा सीट पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों के लोग भाजपा से जुड़े है बूथ स्तर तक मजबूत करना है।

उद्घाटन सत्र के बाद श्री मंगल पांडेय ने प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में केंद्र सरकार की योजनाओं एवं राज्य के हर बूथ पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर किया गया है।

इस बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता श्री राजीव प्रताप रुडी, श्री शाहनवाज हुसैन, श्री शत्रुघ्न सिन्हा, श्री राधा मोहन सिंह, डॉ. सीपी ठाकुर, विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री नंदकिशोर यादव, प्रदेश भाजपा महामंत्री (संगठन) श्री नागेंद्रजी समेत भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।■